संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

वर्ष-22 अंक- 249
पृष्ठ 8
शनिवार
30 मई 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

# शहर समता

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- इन लोगों के लिए नुकसानदायक...

विचार- राहुल गांधी से इतना क्यों डरती...

खेल- मानसिक तनाव, असहयोग या फिर...

### मऊ में मुख्यमंत्री योगी बोले

# धार्मिक आयोजन में व्यवधान डालने वाले का रावण और कंस जैसा होगा हाल

मऊ,संवाददाता। मऊ में सीएम योगी ने सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा– अब कोई माफिया खुली जीप से हिंदुओं को धमका नहीं सकता। न ही पिस्तौल लहरा सकता है। सपा सरकार गुंडों के सामने नाक रगड़ती थी। योगी ने मऊ में हुए दंगों का जिक्र भी किया। दरअसल, मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो खुली जिप्सी में एके–47 लिए घूमता दिखा था। हालांकि, योगी ने दंगे की घटना का जिक्र करते हुए किसी का नाम नहीं लिया। पहले की सरकार माफिया के सामने नतमस्तक थी। अराजकता का तांडव था। अब मैं कह सकता हूं कि किसी माफिया और गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व में व्यवधान या उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ, कथा में, किसी

धार्मिक आयोजन में किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनेगा, लेकिन उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी तय है। सीएम योगी शुक्रवार को मऊ के मधुबन पहुंचे थे। यहां उन्होंने 392 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम को सुबह 10.30 बजे कार्यक्रम में पहुंचना था। लेकिन खराब मौसम की वजह से वह करीब 11 बजे पहुंचे। जो लोग यहां 30–35 साल से बड़े होंगे, उन्हें याद होगा कि 2005 में 21 साल पहले इसी मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे। सरकार माफिया के सामने नतमस्तक थी। मऊ की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव होता था। विकास के कार्य नहीं होते थे लेकिन चंदा जुटा–जुटाकर वह कहीं पर कोई धार्मिक आयोजन किया जाता था, रामलीला, यज्ञ , रामनवमी, शिवरात्रि का आयोजन नहीं होने दिया जाता था। उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, शोहदे परेशान किया करते थे। कभी भी अपहरण हो जाता था। व्यापारी सूर्यास्त के पहले दुकान बंद करने को मजबूर होता था। सूर्यास्त के बाद घर का कोई सदस्य घर नहीं पहुंचता था तो परिवार परेशान हो जाता था कि न जाने उसके साथ क्या हो जाए। उस दंगापूर्ण माहौल में, अराजकता से पूर्ण माहौल में पहचान का संकट यहां के युवाओं के सामने खड़ा हुआ था। प्रदेश में तो नौकरी नहीं थी। लेकिन प्रदेश के बाहर जाते थे तो यूपी का नाम सुनकर लोग 10 कदम पीछे हटते थे। योगी ने कहा– पहले गरीब के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी। आपने 2014 में देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंपी थी। पिछले 12 साल में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। मोदी जी कहते हैं हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। आप याद करिए इन चारों में सब आ जाते हैं। अगर इन चार का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा। मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, लेकिन यूपी में 2014 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। सपा ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। सपा सरकार माफिया के सामने नाक रगड़ती थी। इनके पसीने छूटते थे, बोली नहीं निकलती थी माफिया के सामने। ये जो आज उपदेश देते फिर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये जो 65 लाख आवास गरीबों को मिला है वो सपा की सरकार में क्यों नहीं मिला। सपा की 4–4 बार सरकार थी तब शौचालय क्यों नहीं बना। कांग्रेस ने तो 50 साल शासन दिया उन्होंने क्यों नहीं किया। गरीबों को तब राशन क्यों नहीं मिला। इन दोनों की सरकारों में राशन गुंडे डकार जाते थे।

### अमित शाह ने भुज में जी-7 चौकी का उद्घाटन कर कहा-

# हमने इस पूरे क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा जाल स्थापित करने में धीरे-धीरे सफलता प्राप्त की

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट जी–7 का उद्घाटन किया और संवेदनशील हरामी नाला क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड को प्रमुख तकनीकी चुनौतियों के बावजूद काफी मजबूत बताया। अपनी यात्रा के दौरान, शाह ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों से बातचीत की और नीम का पौधा लगाया। उद्घाटन समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि जी–7 सुविधा का निर्माण क्षेत्र में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों के तहत लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था। उन्होंने कहा कि यहां से कुछ किलोमीटर दूर, बनासकांठा में, एक केंद्र स्थापित किया गया था ताकि जनता को आप सभी द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों से अवगत कराया जा

सके। इस केंद्र का निर्माण लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था आज जी–7 और जी–13 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। जब मैंने देश के गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो बीएसएफ के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से हरामी नाला असुरक्षित प्रतीत होता है।

शाह ने तकनीकी और भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क स्थापित करने में सरकार की क्रमिक सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे क्षेत्र में एक मजबूत सुरक्षा जाल स्थापित करने में धीरे–धीरे सफलता प्राप्त की है। मैं उन विशाल तकनीकी चुनौतियों से भलीभांति अवगत हूं जिन्हें वर्तमान में हमारे सामने खड़े टावरों के निर्माण के लिए पार करना पड़ा३ सीमा चौकियों के आसपास के पूरे क्षेत्र को जमीन से लगभग 3.75 मीटर ऊपर उठाया गया है३ लगातार तीन महीनों तक, मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन प्रगति की निगरानी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सर्वेक्षण कार्य बाधित न हो।

गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने और विकास एवं सुरक्षा परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं।

## सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को दिए निर्देश, तीन महीने में सुनाना होगा रिजर्व फैसला

नयी दिल्ली,एजेंसी। न्यायिक मामलों में फैसलों की देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष न्यायालय ने देशभर के सभी हाईकोर्टों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है, उनमें यथासंभव तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों, विशेष रूप से जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि जमानत मामलों में आदेश उसी दिन जारी किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से आदेश सुरक्षित रखा जाता है तो उसे अगले दिन तक सुनाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश झारखंड हाईकोर्ट में लंबित कुछ आपराधिक अपीलों की सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सुनवाई पूरी होने के बावजूद दो से तीन वर्षों तक फैसले नहीं सुनाए गए। अदालत ने माना कि ऐसी देरी न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी असर डाल सकती है। पीठ ने कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है।ष इसलिए समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करना न्यायपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरक्षित मामलों में कारणयुक्त निर्णय तीन महीने के भीतर सुनाने का प्रयास किया जाए। यदि किसी मामले में तीन महीने तक फैसला नहीं आता है तो उसे संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि यदि तीन महीने के बाद अतिरिक्त एक माह तक भी फैसला लंबित रहता है तो संबंधित पक्षकार मामले को किसी दूसरी पीठ को सौंपने की मांग कर सकते हैं। जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने, आदेश तुरंत जेल प्रशासन तक पहुंचाने और फैसलों को 24 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि केवल आदेश का सारांश सुनाया गया है तो विस्तृत निर्णय 15 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा।

## जहरीली शराब पीने से एक घर के तीन सदस्यों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत

पुणे,एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से कम से कम 12 लोगों की मौत होने की दर्दनाक घटना सामने आई है। यह मामला हडपसर इलाके के पांढरे माला क्षेत्र का है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शराब पीने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में 28 मई को दो लोगों की मौत हुई और 29 मई को मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया। स्थानीय निवासी सुनंदा साबले ने बताया, श्मरने वाले कई लोग एक बस्ती के रहने वाले थे। इनमें से तीन लोग एक ही घर के थे। एक का नाम अरुण, दूसरे का राहुल और तीसरे का नाम यशवंत था। शराब पीने के करीब 10 मिनट बाद ही उन्हें उल्टी और पेट दर्द शुरू हो गया था। उन्होंने कहा, कल दो लोगों की मौत हुई थी। बाद में एक और शव मिला। एक ही परिवार के तीन लोगों की जान गई है।

### केंद्रीय कानून मंत्री के बयान से हलचल, कहा-

# जनता ही मजबूर करेगी

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि विपक्ष शासित राज्यों पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए जनता का दबाव होगा। उन्होंने कहा कि इस विचार को लंबे समय से संवैधानिक समर्थन प्राप्त है। मेघवाल ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में यह बात कही। यह टिप्पणी उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे भाजपा शासित राज्यों द्वारा यूसीसी कानून पारित करने के बाद आई है। मेघवाल ने कहा कि तीन राज्यों ने पहले ही यूसीसी लागू कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि कई अन्य राज्यों ने भी इस मुद्दे की जांच के लिए समितियां बनाई हैं। मंत्री ने कहा कि यह मुद्दा बहुत लंबे समय से चर्चा में है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माण के समय भी यह मांग मौजूद थी। बाबासाहेब अंबेडकर ने भी देश को इस दिशा में आगे बढ़ने की बात कही थी। हालांकि, उस समय के नेताओं ने इसे

बाद के लिए छोड़ दिया और इसे राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में रखा।

यूसीसी का अर्थ विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और विरासत जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले सामान्य नागरिक कानूनों से है। ये कानून धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होंगे। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। निर्देशक सिद्धांत गैर–न्यायसंगत होते हुए भी शासन और नीति निर्माण में मौलिक माने जाते हैं। मेघवाल से पूछा गया कि क्या कुछ राज्यों के विफल होने पर केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा, मेरा मानना है कि वहां के लोग भी अपनी सरकारों से पूछेंगे कि वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मेघवाल ने स्पष्ट किया कि उनकी स्थिति को केंद्र सरकार द्वारा इस मुद्दे को पूरी तरह से जनता पर छोड़ने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग निश्चित रूप से इसकी मांग करेंगे, भले ही भाजपा सत्ता में न हो। मेघवाल ने कहा, लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि यह कानून आदिवासी समुदायों पर भी लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासी परंपराएं और रीति–रिवाज एक अलग मामला हैं।

## हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत, कई मलबे में दबे

हमीरपुर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। भीषण तूफान के कारण निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबे के नीचे दबकर छह मजदूरों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस बल और स्थानीय निवासी घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। हमीरपुर के एएसपी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया, ष्28 और 29 मई की मध्यरात्रि करीब 2 बजे सूचना मिली कि थाना लालपुर क्षेत्र के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का स्लैब गिर गया है, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और हम सभी तत्काल मौके पर पहुंच गए। अभी तीन लोग खंभे पर फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। छह लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिनमें से पांच लोगों की पहचान कर ली गई है। स्लैब हटाकर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जानकारी के मुताबिक, बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया।

# बंगाल में एक अगस्त से होगी जनगणना: सीएम शुभेंदु

कोलकाता,एजेंसी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में एक अगस्त से जनगणना शुरू होगी। यह प्रक्रिया अगले साल फरवरी के अंत तक चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जनगणना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के कुछ हिस्सों में बदलती आबादी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से बंगाल के कई इलाकों का जनसांख्यिकीय ढांचा बदल गया है। उनके अनुसार, बांग्लादेश के साथ लगी सैकड़ों किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ नहीं लगी है। इसी खुली सीमा की वजह से घुसपैठ हो रही है, जिससे आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। राज्य सचिवालय श्नबन्नाश में हुई एक बैठक के बाद उन्होंने लोगों से इस

प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेहतर शासन और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए जनगणना के सही आंकड़े बहुत जरूरी हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, देश जनगणना के काम में काफी आगे निकल गया है, जबकि पश्चिम बंगाल इस मामले में पीछे रह गया है। अब राज्य को दूसरे राज्यों की बराबरी करनी होगी। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के कुछ हिस्सों में बदलती आबादी पर भी चिंता जताई। उन्होंने इसका मुख्य कारण सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की 600 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ नहीं लगी है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि जमीन न देने के कारण बीएसएफ वहां बाड़ नहीं लगा सकी। इसी खुली सीमा की वजह से घुसपैठ हुई और राज्य के कई इलाकों का जनसांख्यिकीय ढांचा बदल गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बंगाल के हर नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए।

## भारत के मूल्यों के खिलाफ है सरकार का रुख

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस्राइल के प्रति कथित रूप से एकतरफा समर्थन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का रुख भारत की पारंपरिक विदेश नीति और मानवीय मूल्यों के विपरीत है व यह करोड़ों भारतीयों के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह विवाद उस समय सामने आया जब इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक कथित बयान का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि नेतन्याहू ने एक सम्मेलन में दावा किया कि दुनिया के अधिकांश देशों में इस्राइल की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस्राइल के सबसे मजबूत समर्थक के रूप में सामने आए हैं।

# शादी करके बहू और उसके परिवार का अपमान क्यों ? दहेज प्रताड़ना मामले में अदालत की सख्त टिप्पणी

नई दिल्ली,एजेंसी। दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आखिर लड़के शादी क्यों करते हैं, अगर बाद में लड़की और उसके परिवार का अपमान ही करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि बहू और उसके परिवार को प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ

छत्तीसगढ़ के एक दहेज मौत मामले की सुनवाई कर रही थी। मामला एक महिला की शादी के तीन साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से मौत से जुड़ा था। अदालत ने कहा कि दहेज के लिए मानसिक और आर्थिक दबाव डालना बेहद गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त संदेश देना जरूरी है। यह मामला वर्ष 2010 का है। आरोप था कि महिला के पति और ससुराल वालों ने लगातार दहेज की मांग की। परिवार से नकद रकम और कार मांगी जा रही थी। अदालत को बताया गया कि महिला के परिवार ने कई बार पैसे देकर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। बाद में महिला की फांसी लगने से मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई। ट्रायल कोर्ट ने माना कि शादी के सात साल के भीतर असामान्य मौत हुई और उसके पहले लगातार प्रताड़ना दी गई।

## हाईवे पर बस और कार की भिड़ंत में दंपती समेत तीन की मौत, सैदाबाद में हुआ हादसा

प्रयागराज। हंडिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर बाद बड़ा हादसा हो गया। सैदाबाद के पास भेस्की गांव में हाईवे पर कार और बस की जोरदार भिड़ंत में कार सवार दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बेटे की हालत नाजुक बनी हुई

है। हंडिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोपहर बाद बड़ा हादसा हो गया। सैदाबाद के पास भेस्की गांव में हाईवे पर कार और बस की जोरदार भिड़ंत में कार सवार दंपती समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसा इतना भीषण था कि बस से टकराने के बाद कार खड्ड में गिर गई।

## सात साल की उम्र में इश्क पर लिखा शेर, पिता से मिली पिटाई और दुनिया से तालियां

प्रयागराज। 15 फरवरी 1935 को जन्मे और मूलतः अयोध्या (तब फैजाबाद) के बकिया गांव के रहने वाले डॉ. बशीर बद्र ने सात साल की उम्र में पहला शेर लिखा था... 'हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूं/तेरे इश्क में, मैं मरा जा रहा हूं।' 15 फरवरी 1935 को जन्मे और मूलतः अयोध्या (तब फैजाबाद) के बकिया गांव के रहने वाले डॉ. बशीर बद्र ने सात साल की उम्र में पहला शेर लिखा था... 'हवा चल रही है उड़ा जा रहा हूं/तेरे इश्क में, मैं मरा जा रहा हूं।' इस पर पिता ने उनकी खूब पिटाई की थी। साथ ही शायरी से दूर रहने की हिदायत दी थी। आगे चलकर मुशायरे की दुनिया में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। डॉ. बशीर बद्र को वर्ष 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने उन्हें 'मीर तकी मीर अवार्ड' प्रदान किया। डॉ. बशीर बद्र का आशियाना कभी शहर के

दायराशाह अजमल मोहल्ले में हुआ करता था। तब के इलाहाबाद में छह साल रहकर उन्होंने पुलिस मुख्यालय में लिपिक के पद पर काम किया। हिंदुस्तानी साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका गुफ्तगू के संस्थापक डॉ. इम्तियाज अहमद गाजी बताते हैं कि प्रयागराज के दायराशाह अजमल के अजमल अजमली से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इस वजह से वह वहीं रहते थे। वर्ष 1961 से 1967 तक उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशकीमती समय प्रयागराज में ही बिताया। उनका दुनिया से जाना मुशायरे की दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। प्रयागराज छोड़ने के बाद वर्ष 2005 में वे आखिरी बार यहां के उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित मुशायरे में शामिल हुए थे। हालांकि, इससे पहले भी वह मुशायरों में शामिल होने बराबर प्रयागराज आते रहे थे। मुशायरे में उनकी मौजूदगी कार्यक्रम की कामयाबी की गारंटी हुआ करती थी। साहित्यकार एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में शिक्षक रहे प्रो. अली अहमद फातमी बताते हैं कि 1974–75 की बात है, जब डॉ. बशीर बद्र शेरवानी फैक्ट्री में मुशायरे में शामिल होने आए थे। वह फिराक गोरखपुरी से मिलना चाहते थे। उस वक्त प्रो. फतमी विश्वविद्यालय में शोधार्थी थे। डॉ. बशीर के कहने पर वह उन्हें फिराक गोरखपुरी के पास ले गए। बताया कि कोई मिलने आया है। फिराक साहब ने डॉ. बशीर बद्र से बहुत ही अदब से पूछा कि क्या शायरी करते हो? डॉ. बशीर उस वक्त मुशायरे में काफी नाम कमा चुके थे।

डॉ. बद्र कहते थे, मैं तो सप्लाई इन डिमांड का शायर हूं

साहित्यकार प्रो. अली अहमद फातमी बताते हैं कि 70 व 80 के दशक में डॉ. बशीर बद्र काफी बड़ा नाम हुआ करता था। डॉ. बद्र जब भी उनसे मिले तो यही कहते कि वह तो सप्लाई इन डिमांड के शायर हैं। श्रोताओं को जो पसंद है, वही सुनाते हैं। प्रो. फातमी का मानना है कि डॉ. बशीर के जाने से 'पॉपुलर मुशायरे' को हुई क्षति की भरपाई अब मुश्किल है।

भोपाल में हुई थी प्रो. फातमी की आखिरी मुलाकात

प्रो. अली अहमद फातमी ने बताया कि आठ साल पहले वह मध्य प्रदेश सरकार से अवार्ड लेने भोपाल गए थे, तब डॉ. बशीर बद्र से उनकी मुलाकात हुई थी। डॉ. बशीर काफी बीमार थे और बहुत कुछ भूल चुके थे। काफी याद दिलाने पर थोड़ा बोले और फिर उन्हें काफी देर तक निहारते रहे। साहित्यकार रविनंदन सिंह बताते हैं कि डॉ. बशीर बद्र का जीवन अनेक संघर्षों से गुजरा। 1987 के मेरठ दंगों की आग में उनका घर और निजी पुस्तकालय जल गया। इस घटना ने उनके मन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इस पीड़ा की छाया उनकी अनेक गजलों और शेरों में दिखाई देती है। व्यक्तिगत दुख को उन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति बना लिया। उसी दौर में उन्होंने यह मशहूर शेर लिखा था, 'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में।' मुशायरे की दुनिया में 1974 से 1990 के बीच का दौर उनके रचनात्मक जीवन का अहम समय माना जाता है। इसी दौरान उनकी शायरी ने देश और विदेश में पहचान बनाई। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।

## हाईकोर्ट का अहम फैसला– चार्जशीट के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अदालत मामले का संज्ञान लेकर ट्रायल शुरू कर चुकी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अदालत मामले का संज्ञान लेकर ट्रायल शुरू कर चुकी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई योग्य नहीं रहेगी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ललितपुर निवासी नीरज याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि दहेज हत्या व अन्य मामले में गिरफ्तारी के समय उसे कानूनी आधार नहीं बताए गए और परिजनों को सूचना भी नहीं दी गई, जिससे स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन हुआ। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि चार्जशीट दाखिल होने, अदालत की ओर से संज्ञान लेने और आरोप तय होने के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में वैध रूप से बंद है।

# शंकरगढ़ का जल संकट- पानी का एक गड्ढा, जहां से इन्सान भी पीते हैं और कुत्ते भी

प्रयागराज। बारा तहसील की शंकरगढ़ नगर पंचायत में आप घूमिए और किसी से जीवन की समस्याएं पूछिए तो यही कहेगा, सिर्फ पानी चाहिए। यह रट आज की नहीं वर्षों पुरानी है। बारा तहसील की शंकरगढ़ नगर पंचायत में आप घूमिए और किसी से जीवन की समस्याएं पूछिए तो यही कहेगा, सिर्फ पानी चाहिए। यह रट आज की नहीं वर्षों पुरानी है। संकट का चरम यह है कि ओसा ग्राम पंचायत के एक मजरे में पत्थरों के बीच एक गड्ढा है, जहां पहाड़ों से रिसकर पानी जमा होता है। बस्ती के लोग भी इसे पीते हैं और कुत्ते भी। तहसील मुख्यालय से भेलांव और तेलघना गांव होते हुए आगे बढ़ने पर करीब 14 किमी की दूरी पर ओसा गांव स्थित है। यहां के प्राथमिक विद्यालय के ठीक पीछे करीब पांच सौ मीटर दूरी पर ओसा पहाड़ी है। यहां एक मजदूरी पेशा लोगों की छोटी बस्ती है। बजुर्ग रामलाल बताते हैं कि हम सब को बेसहारों की तरह छोड़ दिया गया। उम्र बीती जा रही है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं।

वहां बने गड्ढे को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि इसी चूहड़ (स्थानीय नाम) का गंदा पानी हम सब पीते हैं। कुत्ते भी यहीं अपनी प्यास बुझाते हैं। आखिर वे जाए कहां। दोपहर के समय कई महिला और पुरुष वहां पानी भर रहे थे। उनमें से एक घर की बहू सोनू सामने आई। बोली कि पानी के लिए सुबह से शाम तक हम कई चक्कर इस चूहड़ के लगाते हैं। पीछे से कई महिलाओं ने सुर भरा।

राजबहादुर और बल्ले ने बताया कि कई साल पहले एक

बोर कराया गया था लेकिन काम न आया। ग्राम प्रधान गणेश कुमार भी समस्या को स्वीकारते हैं। पानी की यह समस्या सिर्फ एक गांव की नहीं, शंकरगढ़ के 76 गांवों की है। हालांकि, यह मानव जनित से ज्यादा भूसंरचना की देन है। क्योंकि यह क्षेत्र पथरीली पहाड़ियों का है। लोगों को दुख इस बात का है कि इनकी समस्या को दूर करने के लिए जो भी योजनाएं बनीं, उन्हें अमल में लाने के लिए कोई ठोस काम न हुआ।

कपड़े से छानकर पीते हैं पानी

राजेंद्र कहते हैं कि चूहड़ का पानी बहुत गंदा होता। इसे कपड़े से छानते हैं फिर भी साफ नहीं होता। बदबू भी आती है लेकिन प्यास बुझाना मजबूरी है। राजबहादुर ने बताया कि इसकी वजह से इस गांव के लोगों को पेट की समस्या होती है। दिन में करीब दस किमी दूर जाकर दिखाना पड़ता है।

जब सूख जाता है चूहड़...

बस्ती एक महिला, जिसे सभी बुआ कहते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादा गर्मी पड़ने पर चूहड़ में पानी सूख जाता है। तब कम से कम एक किलोमीटर दूर जाकर एक हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है। जेठ की दोपहरी में ऊबड़–खाबड़ रास्ते से पैदल जाना पड़ता है। एक बार में ज्यादा से ज्यादा दो डिब्बा पानी ला पाते हैं। इसलिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

– सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की रिपोर्ट के अनुसार जब भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे हो तो स्थिति गंभीर मानी जाती है।

– शंकरगढ़ क्षेत्र का भूजल स्तर 80 मीटर है। गर्मी में तो अधिकतर स्थानों पर करीब 100 मीटर से भी नीचे चला जाता है।

– सीजीडब्ल्यूबी के अनुसार शहरी क्षेत्र के एक व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर पानी चाहिए और ग्रामीण व्यक्ति को 55 लीटर।

– शंकरगढ़ में कई गांव ऐसे हैं, अनुमानतः जहां पूरे परिवार को 55 से 70 लीटर पानी मिल पाता है। वह भी उनकी मेहनत से।

एक नजर

शंकरगढ़ के 12 वार्डों की जनसंख्या लगभग 25000

ओसा ग्राम पंचायत की आबादी 2400

गांव में 20 हैंडपंप, तीन खराब हैं

कुछ लोगों ने निजी व्यवस्था की है

नगर में 25 सरकारी समरसेबल पंप लगे हैं। 20 टैंकर से पानी सप्लाई की व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर अतरिक्त टैंकर भेजा जाता है।

– पार्वती कोटार्य, शंकरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष

# 25 हजार की इनामी बीएसए शालिनी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक के आत्महत्या मामले में फरार चल रहीं देवरिया के पूर्व बीएसए शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरार बीएसए के ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 हजार की इनामी देवरिया की तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र में अवैध वसूली को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सरकारी कार्यालयों को "आदेश बेचने की खुली दुकान" नहीं बनने दिया जा सकता। कोर्ट ने माना कि मामले में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं और जांच में मिले साक्ष्य आवेदिका के खिलाफ आरोपों को समर्थन देते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकलपीठ ने दिया है।

मामला देवरिया के शिक्षक कृष्ण मोहन सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है। शिक्षक की पत्नी की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात क्लर्क संजीव सिंह और बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पक्ष में आदेश पारित करने के बदले तीन शिक्षकों से 16–16 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के अनुसार रुपये देने के बावजूद लगातार और धन की मांग तथा मानसिक उत्पीड़न किया गया, जिससे परेशान होकर शिक्षक ने आत्महत्या कर ली।

अभियोजन के अनुसार मृतक कृष्ण मोहन सिंह, ओंकार सिंह और अपर्णा तिवारी वर्ष 2016 में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए थे। बाद में उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फरवरी 2025 में हाईकोर्ट ने निरस्तीकरण आदेश रद्द कर मामले पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था। आरोप है कि इसी आदेश के अनुपालन के लिए बीएसए कार्यालय में रिश्वत मांगी गई।

कोर्ट के समक्ष पेश आत्महत्या पत्र में मृतक ने विस्तार से लिखा कि तीनों शिक्षकों से पहले 20–20 लाख रुपये मांगे गए, बाद में सौदा 16–16 लाख रुपये पर तय हुआ। सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख है कि रकम जुटाने के लिए शिक्षकों ने जमीन गिरवी रखी, गहने बैंक में जमा किए और रिश्तेदारों से उधार लिया। मृतक ने लिखा कि लगातार दबाव, अपमान और वसूली से वह टूट चुका था।

शिक्षक ने लिखा था चार पन्नों का सुसाइड नोट

जांच के दौरान पुलिस को चार पन्नों का सुसाइड नोट, ऑडियो क्लिप, वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज मिले। एक वीडियो में मृतक ने कथित तौर पर कहा कि "16 लाख रुपये बीएसए मैडम ने ले लिए" और इसके बावजूद उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच

अधिकारी ने सहकर्मी शिक्षक ओंकार सिंह का बयान भी दर्ज किया, जिसमें कथित रिश्वतखोरी की पूरी प्रक्रिया और रकम देने का विवरण सामने आया।

शालिनी श्रीवास्तव की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि सुसाइड नोट में उनका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया और आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई ठोस आरोप नहीं बनता। यह भी कहा गया कि उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हाईकोर्ट ने बीएसए पर की तल्ख टिप्पणी

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि जांच में मिले ऑडियो–वीडियो साक्ष्य, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज रिश्वत मांगने और मानसिक उत्पीड़न की पुष्टि करते हैं। अभियोजन ने अदालत को बताया कि मृतक 20 फरवरी 2026 को बीएसए कार्यालय गया था, जहां उसे प्रताड़ित किया गया और अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली।

कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए किसी आरोपी की स्वतंत्रता सीमित करनी पड़े तो अदालतों को इससे हिचकना नहीं चाहिए।

कोर्ट ने अपने आदेश में बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों को आदेश बेचने की खुली दुकान नहीं बनने दिया जा सकता। अदालत ने माना कि मृतक और अन्य शिक्षकों से अवैध धन उगाही के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उपलब्ध साक्ष्यों से यह नहीं लगता कि आवेदिका को झूठा फंसाया गया है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

## 2027 तक 13 मीटर नीचे जा सकता है भूजल, एमएनएनआईटी के शोध में खुलासा

प्रयागराज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना–कृष्णी दोआब इलाके में भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह लगातार पानी निकाला जाता रहा तो साल 2027 तक कई जगहों पर भूजल स्तर करीब 13.42 मीटर तक नीचे पहुंच सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यमुना–कृष्णी दोआब इलाके में भूजल तेजी से नीचे जा रहा है। अगर इसी तरह लगातार पानी निकाला जाता रहा

तो साल 2027 तक कई जगहों पर भूजल स्तर करीब 13.42 मीटर तक नीचे पहुंच सकता है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. राजमोहन सिंह, प्रवीन कुमार और अनुराग यादव के शोध में यह जानकारी सामने आई है। यह शोध करेंट साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक शामली, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद जैसे पश्चिमी यूपी के शहरों में खेती, घरों और उद्योगों के लिए भूजल सबसे बड़ा जल स्रोत है लेकिन बढ़ती आबादी और जरूरतों के कारण लगातार ज्यादा पानी निकाला जा रहा है। इसी वजह से भूजल स्तर हर साल गिरता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के करीब 85 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों की पानी की जरूरत भूजल से ही पूरी होती है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सॉइल एंड वाटर असेसमेंट टूल (स्वाट) और मॉडफ्लो जैसे कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल किया। इनकी मदद से यह समझने की कोशिश की गई कि बारिश का पानी जमीन में कितना जा रहा है, कितना बह रहा है और भूजल पर उसका क्या असर पड़ रहा है। इस दौरान यह पता चला कि कुल बारिश का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा ही भूजल के रूप में जमीन के अंदर पहुंच पा रहा है। वहीं करीब 34 प्रतिशत पानी सतही बहाव में चला जाता है और लगभग 47 प्रतिशत पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है।

## ग्राइंडर मशीन से गला रेतकर युवक ने कर ली आत्महत्या, पत्नी से चल रहा था विवाद

प्रयागराज। फूलपुर कस्बे में उसे समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने ग्राइंडर से गला रेतकर आत्महत्या कर ली। घटना से घर में कोहराम मच गया है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। फूलपुर कस्बे में उसे समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने ग्राइंडर से गला रेतकर आत्महत्या कर ली।

घटना से घर में कोहराम मच गया है। पुलिस की जांच में प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह की बात सामने आई है। फूलपुर कस्बे के कोहना मोहल्ला निवासी शाहरुख उर्फ अतीक (30) पुत्र मोहम्मद हबीब की शादी तीन वर्ष पहले हुई थी। उसके एक बेटा भी है। परिजनों ने बताया कि अतीक का पति–पत्नी के बीच काफी दिनों से पारिवारिक न्यायालय में विवाद चल रहा था। परिजनों ने बताया कि उसने परामर्श केंद्र में भी आवेदन किया था। जिस पर उसकी पत्नी अभी एक दिन पहले ही घर लौटी थी। परिजनों के मुताबिक रात करीब 2 बजे के बाद युवक ने घर में रखी ग्राइंडर मशीन को गले पर लगाकर चालू कर दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार मे चीख पुकार मच गई। मौके पर आसपास के लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव से जुड़ा सामने आ रहा है। पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है।
–विवेक यादव, सहायक पुलिस आयुक्त, फूलपुर

## एसआरएन अस्पताल में सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं का रास्ता साफ

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को एक रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 90 वर्ष के लिए 31,314 वर्ग मीटर जमीन स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल को पट्टे पर दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को एक रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 90 वर्ष के लिए 31,314 वर्ग मीटर जमीन स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल को पट्टे पर दे दिया है। डीएम मनीष कुमार वर्मा की ओर से आवश्यक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अब प्रयागराज में सुपरस्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाओं का रास्ता साफ हो गया है। राजकीय अस्पताल होने के नाते प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट, भदोही, फतेहपुर, बांदा समेत आसपास के अन्य जिलों से यहां आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी।

एसआरएन अस्पताल में मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने आते हैं। हालांकि, सुविधाओं के विस्तार के दौरान निर्माण की जद में आ रहे मुख्य विकास अधिकारी समेत कई अफसरों के सरकारी आवास को गिराना पड़ेगा। विकल्प तलाशने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गए हैं और जमीन एसआरएन अस्पताल को 90 वर्षों के लिए लीज पर दे दी गई है। अफसरों के सरकारी आवास के लिए किसी दूसरी जगह जमीन तलाशी जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों की मदद की जाएगी। – मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी डीएम मनीष कुमार वर्मा ने 23 मई को एसआरएन अस्पताल के निरीक्षण के दौरान ट्रामा सेंटर को परिसर में ही किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव मांगा था। जमीन लीज पर दिए जाने के बाद अब ट्रामा सेंटर को अस्पताल परिसर में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। एसआरएन अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। ऐसे में वहां पार्किंग की समस्या बनी रहती है और अस्पताल परिसर में आवागमन में काफी दिक्कत होती है। एसआएन अस्पताल को लीज पर जमीन मिलने के बाद पार्किंग की समस्या से भी राहत मिलेगी। एसआरएन अस्पताल परिसर में नए चिल्ड्रेन अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। चिल्ड्रेन अस्पताल में कराए जा रहे गैस पाइप लाइन, ऑक्सीजन पाइप लाइन व बेड हेड पैनल का कार्य जून माह तक पूरा किए जाने लक्ष्य है। डीएम ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए सितंबर तक चिल्ड्रेन अस्पताल को पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया जाए।

## राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोपी को मिली जमानत, 11 माह से जेल में है बंद

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का महिमामंडन करने के आरोपी वासिक त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का महिमामंडन करने के आरोपी वासिक त्यागी को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने दिया है। मुजफ्फरनगर निवासी याची के खिलाफ चरथावल थाने में विभिन्न आरोप में एफआईआर दर्ज है। वह सात जून 2025 से ही जेल में बंद है। उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद'। हाईकोर्ट ने देवरिया में तैनात शिक्षक की आत्महत्या के मामले में आरोपी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अनिरुद्ध सिंह को जमानत दे दी है। गोरखपुर के गुलरिहा थाने में शिक्षक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि सहायक शिक्षक ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव और पूर्व प्रधानाध्यापक अनिरुद्ध सिंह पर कई आरोप लगाए गए थे।

## स्क्रूटनी में नंबर बढ़ाने का झांसा दें रहें साइबर ठग, यूपी बोर्ड ने जारी किया अलर्ट

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने वाले छात्र–छात्राओं और उनके अभिभावकों को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने वाले छात्र–छात्राओं और उनके अभिभावकों को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। पैसे लेकर अंक बढ़ाने का झांसा देकर ठग अभ्यर्थियों को फोन कॉल, मैसेज और ईमेल के माध्यम से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, साइबर अपराधी खुद को माध्यमिक शिक्षा परिषद का कर्मचारी या अधिकारी बताकर अभ्यर्थियों से संपर्क कर रहे हैं। वे स्क्रूटनी में नंबर बढ़ाने का लालच देकर रुपये मांग रहे हैं। इसके लिए परिषद के कर्मचारियों के नाम और पदनाम का भी दुरुपयोग किया जा रहा है।

## संक्षिप्त

### चौ.चरण सिंह के सिद्धांत और विचार रालोद की प्रेरणा-रामाशीष

लखनऊ (संवाददाता)। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश मुख्यालय पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा एवं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय ने चौधरी साहब को नमन करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह का संपूर्ण जीवन किसानों, मजदूरों एवं गांवों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। उनके सिद्धांत और विचार राष्ट्रीय लोकदल की प्रेरणा हैं। राष्ट्रीय लोकदल सदैव किसानों के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है और आज एनडीए सरकार में भी किसानों से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाकर किसानों के हित में निर्णय करवाने का कार्य कर रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान, फसलों का उचित मूल्य, सिंचाई, बिजली एवं ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल लगातार संघर्षरत है। चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चलते हुए राष्ट्रीय लोकदल गांव, किसान, मजदूर और नौजवानों के अधिकारों की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहेगा। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम हैदर, आदित्य विक्रम सिंह, रजनीकांत मिश्रा, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह चौहान, प्रीति श्रीवास्तव, चंद्रकांत अवस्थी, राघवेंद्र प्रताप यादव, युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

### निपुण भारत मिशनः योगी सरकार जिला समन्वयकों को देगी विशेष ट्रेनिंग

लखनऊ (संवाददाता)। योगी आदित्यनाथ सरकार अब निपुण भारत मिशन और गुणवत्ता शिक्षा अभियान को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य स्तर पर कार्यरत जिलासमन्वयक निपुण भारत मिशन एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित जिला समन्वयकों की प्रशिक्षण में अनिवार्य सहभागिता संबंधी निर्देश दिए गए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी लखनऊ में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों से जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे।प्रशिक्षण का उद्देश्य निपुण भारत मिशन और गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। निपुण भारत मिशन एक शैक्षिक कार्यक्रम के साथ बच्चों की सीखने की बुनियादी क्षमता को सुदृढ़ करने का व्यापक अभियान है। योगी सरकार ने पिछले एक दशक में परिषदीय शिक्षा के ढांचे, तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था और शिक्षण पद्धतियों में व्यापक सुधार किए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, स्मार्ट क्लास, डिजिटल मॉनिटरिंग, ई-कंटेंट और निपुण भारत मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में बड़े परिवर्तन लाए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो बैचों में होगा। पहले बैच का प्रशिक्षण 1 जून को होगा, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, देवीपाटन, गोरखपुर, चित्रकूट मंडल के जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। दूसरे बैच का आयोजन 2 जून को किया जाएगा, जिसमें झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी मंडल के जिला समन्वयक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। जिला स्तर पर अकादमिक मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, तभी विद्यालयों में सीखने के परिणामों में वास्तविक सुधार दिखाई देगा।

### योगी सरकार की पहल, अनाज खरीद में रिकॉर्ड भुगतान

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में खाद्य तथा रसद विभाग ने किसानों और गरीब परिवारों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच का काम किया है। रबी विपणन वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित किया गया। 51,70,117 किसानों को लाभ मिला। योगी सरकार की ओर से किसानों को 45,935.46 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद को सुचारु बनाने के लिए 5,837 गेहूं क्रय केंद्र संचालित किए गए, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने में सहूलियत मिल रही है। खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीद के क्षेत्र में प्रदेश ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2017-18 से 2025-26 तक धान खरीद से 80,39,539 किसानों को लाभ पहुंचाया गया। किसानों को इसके बदले 1,03,694.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 एवं 2025-26 के अंतर्गत ज्वार खरीद से 26,972 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 363.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। बाजरा खरीद से 1,48,718 किसानों को फायदा पहुंचा और उन्हें 1,854 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। योगी सरकार केवल गेहूं और धान तक सीमित नहीं रही बल्कि अन्य फसलों की खरीद को भी बढ़ावा दिया गया।

### लखनऊ हुआ फिल्म ड्रॉप आउट का विशेष प्रमोशन

लखनऊ (संवाददाता)। हिंदी फीचर फिल्म ड्रॉप आउट के प्रमोशन के लिए लखनऊ स्थित गैंगवार इंस्टीट्यूट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य अतिथियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फिल्म की हीरोइन तनुष्का ने फिल्म की कहानी को लेकर बताया कि यह एक ग्रामीण युवा की है जिसे श्ड्राप आउटश करना पड़ता है। उसकी जिंदगी में आस्था नामक लड़की आती है,जो उसे निराश होने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।मीडिया से मुखातिब हीरोइन तनुष्का ने कहा कि मेरा मानना है कि ड्रॉप आउट असल में श्इंडश्प्वाइंट नही बल्कि कुछ बेहतर करने का मौका है।हमे बिना हताश हुए आगे बढ़ने की जरुरत है, मंजिल जरूर मिलेगी। युवक आखिर कामयाब होता है।तनुष्का कहती है कि यह फिल्म हर दर्शक को अपनी कहानी लगेगी।फिल्म को एक बार देखें जरूर, लगेगा समस्याओं से निपटने के लिए हमे अपने प्रयास सतत जारी रखनी है।यह फिल्म पारिवारिक है, दर्शक कुछ सीखकर ही निकलेंगे।कार्यक्रम के दौरान फिल्म ष्ड्रॉप आउटष के ट्रेलर, गीतों एवं विशेष दृश्यों का प्रदर्शन किया गया। दर्शकों ने फिल्म के विषय, प्रस्तुति और सामाजिक सरोकारों को सराहा तथा इसकी कहानी को युवाओं से जुड़ा हुआ और प्रेरणादायक बताया। फिल्म ड्रॉप आउट के निर्माता उमाशंकर यादव हैं तथा निर्देशन ओंकार पेठकर ने किया है। फिल्म में तनुष्का शर्मा और उदय सिंह प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म शिक्षा, युवाओं के सपनों, करियर के दबाव और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे विषयों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। ड्रॉप आउट 29 मई से देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है।

# प्रशासन की साख दांव पर, पीडीए की सील तोड़ दबंग ने दी खुली चुनौती, सिविल लाइंस पुलिस की 'मेहरबानी' पर उठे सवाल

**बड़ा सवालः पुलिस अभिरक्षा में सौंपे गए परिसर की सील कैसे टूटी। शासन ने तलब की रिपोर्ट, 'रासुका' और 'कुर्की' जैसी सख्त कार्रवाई की तैयारी**

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासनिक नियमों और जमीनी कार्रवाई को सरेआम ठेंगा दिखाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्टैनली रोड पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा सील किए गए एक अवैध परिसर की सील को तोड़कर एक दबंग ने सीधे तौर पर सूबे की सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली भूमिका सिविल लाइंस पुलिस की सामने आ रही है, जिसकी घोर लापरवाही और शिथिलता के कारण आरोपी के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय जनता में अब दबी जुबान यह चर्चा आम है कि प्रशासनिक नियम-कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाले इस रसूखदार पर पुलिस आखिर क्यों मेहरबान है।

सालों से चल रही थी कानूनी प्रक्रिया

प्राप्त विवरण के अनुसार, भवन संख्या-8 पार्ट, स्टैनली रोड पर जीत लाल यादव द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के दो मंजिला अवैध निर्माण कराया गया था। इस पर शिकायत मिलने के बाद पीडीए ने उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 27(1) के तहत 16 जून 2021 को श्कारण बताओ नोटिसश जारी किया था।

निर्माणकर्ता द्वारा न तो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और न ही वह सुनवाई पर उपस्थित हुआ। इसके बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 नवंबर 2021 को अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश जारी किया था।

नोटिस के बावजूद विपक्षी द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया और वह उसी में निवास करता रहा। स्थिति को देखते हुए पीडीए ने अधिनियम की धारा-28(क) के तहत सीलिंग का आदेश पारित किया। इसके अनुपालन में बीते 18 मई 2026 को प्राधिकरण की टीम ने भारी बल के साथ मौके पर पहुंचकर

उक्त अवैध निर्माण को पूरी तरह सील कर दिया था।

नियमानुसार, सील किए गए इस परिसर को बकायदा सिविल लाइंस पुलिस की अभिरक्षा में सौंपा गया था ताकि वहां दोबारा कोई गतिविधि न हो सके। लेकिन अधिकारियों को चुनौती देते हुए विपक्षी/निर्माणकर्ता ने स्थल पर प्रशासन द्वारा लगाई गई सरकारी सील को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और पुनः परिसर के भीतर काबिज हो गया।

सील से छेड़छाड़ यानी सीधे सूबे की सरकार को चुनौती

यह मामला सिर्फ एक अवैध निर्माण या सील टूटने का नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की श्सख्त कानून व्यवस्थाश और भू-माफियाओं के खिलाफ जारी श्जीरो टॉलरेंसश की नीति को खुली चुनौती है। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर शासन स्तर तक अवैध निर्माणकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश हैं, ऐसे में जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे सरकारी सील का टूटना बेहद गंभीर है।

इस घटना के बाद लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक जवाबदेही तय कर दी गई है – सूत्र

पुलिस की भूमिका संदिग्ध रू पुलिस अभिरक्षा में दिए गए परिसर की सील टूट जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। सूत्रों के अनुसार, इस लापरवाही को शासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। यदि सिविल लाइंस पुलिस इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल नहीं भेजती है, तो संबंधित पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरना तय है।

प्रशासन की सीधी जिम्मेदारीः जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर के स्तर पर अब इस मामले की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की जा रही है। मौके पर चौबीस घंटे कड़ा पहरा या सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने की तैयारी है, ताकि दोबारा कोई वहां फटकने की भी जुर्रत न कर सके।

वैधानिक चेतावनी, कानून की जद में आएगा सील को छूने वाला हर हाथ

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 और भारतीय न्याय संहिता के तहत सरकारी सील को क्षतिग्रस्त करना एक गैर-जमानती और गंभीर संज्ञेय अपराध है।

स्पष्ट संदेशः शासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि अब यदि किसी भी व्यक्ति, उसके मददगार या किसी रसूखदार ने सरकारी सील या संपत्ति को छूने की 'हिमाकत' भी की, तो उसे सीधे राजद्रोह और सरकारी कार्य में बाधा डालने का दोषी माना जाएगा। प्रशासन अब ऐसे मामलों में कुर्की और रासुका जैसी कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है, जो भविष्य के लिए एक नजीर बनेगी।

18 मई 2026: पीडीए ने अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया था।

बड़ा अपराधः सरकारी सील को क्षतिग्रस्त करना और सरकारी कार्य में बाधा डालना जेल की सजा का प्रावधान रखता है।

सहयोग करने वाले भी नपेंगेः आरोपी की मदद करने वाले या पैरवी करने वाले रसूखदारों को भी सह-आरोपी बनाकर कानूनी शिकंजे में कसा जाएगा।

# प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना : उप मुख्यमंत्री ने 1 अरब 92 करोड़ 15 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

लखनऊ (संवाददाता)। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत संचालित श्प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27

के लिए कुल घ्192,15,00,000 (1 अरब 92 करोड़ 15 लाख रुपये) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह धनराशि प्रदेश के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नई ऊर्जा देने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। उप मुख्यमंत्री जी द्वारा अलग-अलग अनुदान संख्याओं के तहत बजट का विभाजन बेहद पारदर्शी और वर्ग-वार तरीके से किया गया है। यह राशि मदर सेक्शन के तहत निम्नलिखित श्रेणियों में जारी की जाएगीरू स्वीकृत धनराशि में अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत 167.55 करोड़, अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत घ्2.52 करोड़ तथा अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत 22.08 करोड़ सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 192.15 करोड़ (एक अरब बानवे करोड़ पंद्रह लाख रुपये) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य ध्येय समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह बजट विशेष रूप से सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) के उन लाभार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत जारी यह धनराशि हमारे स्थानीय उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगी। अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि अनुदान की यह राशि बिना किसी बाधा के सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे।

# हमीरपुर हादसे पर सीएम ने जताया शोक

**मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान**

लखनऊ (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल पर हुई दर्दनाक दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने हादसे को अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर रात कई जिलों में तेज आंधी-तूफान, बारिश, आकाशीय बिजली से भारी तबाही का भी संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं।हमीरपुर हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। घायलों को तत्काल बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद को कहा है। राहत कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।गुरुवार देर रात आए तेज आंधी-तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान तथा जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर तीन घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुआवजा वितरण, राहत शिविरों, बचाव अभियान और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने को भी कहा गया है, ताकि आमजन तक सही और समयबद्ध सूचना पहुंच सके। प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

# जनभागीदारी से मिलेगा निराश्रित गोवंश को सहारा

## भूसा दान आदेश नहीं लोक कल्याण अभियान

लखनऊ (संवाददाता)। निराश्रित गोवंशों के लिए भूसा दान को लेकर जारी किए गए पत्र पर बरेली की बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता ने कहा है कि यह आदेश या दबाव नहीं बल्कि लोकहित और जीव सेवा का स्वैच्छिक अभियान है। सनातन संस्कृति, लोक कल्याण और जनभागीदारी की भावना को केंद्र में रखकर चलाए जा रहे इस अभियान को अब समाज का भी व्यापक समर्थन मिलने लगा है। बीएसए कार्यालय की ओर से 22 मई को जारी पत्र में निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसा दान की अपील की गई थी। यह कदम जीव-कल्याण के प्रति मानवीय संवेदना के तहत उठाया गया था, इसे किसी प्रकार के दबाव या आदेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए था।

# चर्चा नव्य विकास की

(छप्पय)

ऊँचे-ऊँचे ख़्वाब शहर ने ज्यों दिखलाए।
छोड़ गाँव का मोह लोभ में सब पगलाए।
गर्दन रही मरोड़ इमारत ऊँची- ऊँची।
सच्ची यह तस्वीर खींचती रहती कूँची।
अहं भाव की साधना चर्चा नव्य विकास की।
काली छाया है बनी जीवन सुखद-विहान की।।

करके बंद किवाड़ शान में ऐसे ऐंठे।
रिश्तों से मुंह मोड़ पड़ोसी घर में बैठे।
शहरी यह तहज़ीब रखे बस उनसे नाता।
लालच में हो चूर नित्य पेड़ों को खाता।
नए आधुनिक दौर की अनुपम यह तस्वीर है।
मौन हवाएँ कह रही मसला अति गंभीर है।।

**डॉ. प्रदीप चित्रांशी**
लूकरगंज, प्रयागराज

## कब्जा मुक्ति हेतु भयहरणनाथ धाम में 12वाँ सामाजिक सत्याग्रह 31 मई को

प्रतापगढ़। प्रसिद्ध पाण्डव कालीन भयहरणनाथ धाम में कब्जा मुक्ति हेतु 12वाँ सामाजिक सत्याग्रह 31 मई 2026, रविवार को धाम परिसर में आयोजित किया जाएगा। नायब तहसीलदार सदर दिनेश चंद्र तिवारी के निजी कार्यों से जनपद से बाहर होने के

कारण गत रविवार को प्रस्तावित सीमांकन व पत्थरगड्डी का कार्यक्रम स्थगित हो गया था। राजस्व कर्मियों ने 31 मई को पुनः उपस्थित होकर कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। भयहरणनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान के महासचिव समाज शेखर ने बताया कि अध्यक्ष राज कुमार शुक्ल एवं कार्यवाहक अध्यक्ष लाल जी सिंह के संयोजन में गत 15 मार्च 2026 से अनवरत सत्याग्रहियों का सामूहिक रचनात्मक प्रयास जारी है। प्रबन्ध संस्था के पदाधिकारी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक 12 वाँ सामूहिक सत्याग्रह जारी रखते हुए राजस्व टीम को पूर्ण सहयोग व भागीदारी का संकल्प व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर धाम में गत 17 मई 2026 से चल रहे मलमास मेला की गतिविधियों के संदर्भ में अपेक्षित आवश्यक चर्चा, समीक्षा एवं आगामी निर्णय भी लिए जाएंगे।

## 2026 का राजमणि देवी स्मृति साहित्य सम्मान प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवान दास मोरवाल को दिया जाएगा

प्रयागराज। साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्था 'संचेतना' का राजमणि देवी स्मृति साहित्य सम्मान (2026) की घोषणा कर दी गई है। यह सम्मान प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवानदास मोरवाल को प्रदान किया जायेगा। यह सम्मान किसी भी रचनाकार को उसके समग्र योगदान पर दिया जाता है। 'काला पहाड़', 'खानजादा' और 'मोक्षवन' आपके चर्चित उपन्यास हैं। इस साल के निर्णायक मण्डल में थेः प्रोफेसर के जी श्रीवास्तव (अध्यक्ष), प्रोफेसर सुनील विक्रम सिंह और उमेश श्रीवास्तव ( संपादक-शहर समता)

## बिजली की आवाजाही छुड़ा रही लोगों के पसीने

लखनऊ (संवाददाता)। बिजली की समस्या से राजधानी के कई इलाके प्रभावित है। बार-बार पावर कट और लो वोल्टेज एक बड़ी समस्या बन रहा है। राजधनी के काकोरी उप-केन्द्र के अर्न्तगत मायापुरम्, जाहिदनगर आलमनगर, बंद्धेश्वर आदि क्षेत्रों के हजारो निवासी बिजली की आंख-मिचौली से खासे परेशान है। इन इलाको में गुरूवार रात ग्यारह बजे से बिजली गायब है। चौदह घंटों के बीत जाने के बाद भी बिजली का कोई अता-पता नहीं है। साथ ही उपकेन्द्र के अधिकारी भी कुछ जानकारी नहीं दे पा रहे है। यह भी जानकारी नहीं दे पा रहे है कि फाल्ट कहां है। फोन मिलाने पर अधिकारी भी रांग नंबर कह कर फोन काट दे रहे है। इतना समय बीत जाने पर घरों में लगे इन्वर्टर भी बेदम हो चुके है। बिजली न आने से लोग पीने के पानी के लिये भी पप्रशान हो रहे है। बिजली पानी की समस्या से परेशान लोग उप-केंद्र का घेराव कर धरना प्रदर्शन का मन बना चुके है।

## फन रिपब्लिक मॉल में शुरू हुआ मैंगो फेस्टिवल आम का सीजन फन का रीजन

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ का प्रसिद्ध शॉपिंग गंतव्य फन रिपब्लिक मॉल इस चिलचिलाती गर्मी में लखनऊवासियों के लिए राहत के आम ले कर आया है जी हां फन रिपब्लिक मॉल में 29 मई से 31 मई तक मैंगो फेस्टिवल धूम मचाएगा । शेफ नंदिनी मोतियानी इस मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगी।फन रिपब्लिक मॉल में 29 मई से 31 मई तक चलने वाले इस मैंगो फेस्ट में ग्राहकों को तीस प्रकार के आमों की खास वैरायटी देखने को मिलेगी जिसमे बंगनपल्ली, अल्फांजो, तोतापुरी, सिंधुरा, मल्लिका, राम केला, लंगड़ा, चौसा, थूरू, सफेदा, केसर, दशहरी इत्यादि किस्म के आम मौजूद रहेंगे। जिसे ग्राहक देखने के साथ साथ खरीद भी सकेंगे। 30 मई को किड्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन जबकि 31 मई यानी अंतिम दिन वूमेन कोल्ड कुकिंग कंपटीशन भी होगा जिसमें मौजूदा आमों से नाना प्रकार के लजीज व्यंजन बनाए जाएंगे। मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रतियोगिताएं ग्राहकों का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करेंगी।फन रिपब्लिक मॉल के जनरल मैनेजर विकल्प सक्सेना ने कहा कि इस गर्मी फलों का राजा आम लखनऊवासियों को ठंड का एहसास कराएगा। हमने देश के कोने कोने से भिन्न भिन्न प्रकार के आमों को मैंगो फेस्ट में लाने का प्रयास किया है। ताकि ग्राहकों को कुछ नया देखने को मिले। 30 प्रकार के आमों की अलग अलग प्रजातियों के आम हम इस फेस्टिवल में लेके आए हैं ताकि ग्राहक सभी प्रकार के आमों का लुफ्त उठा सकें।

# सम्पादकीय.....

## न्यायसंगत आरक्षण

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने से एक महत्वपूर्ण तार्किक चर्चा फिर से प्रारंभ हो गई है। जिसका मकसद है कि कैसे सकारात्मक पहल करके आरक्षण के उद्देश्य को अधिक न्यायसंगत, लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। वास्तव में उनकी पहल का मकसद संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के सबसे गरीब, सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और आरक्षण के लाभ में सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का मकसद पूरा करना। बहुत संभव है कि मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से असहमति के तर्क दिये जाएं। वास्तव में, देश में दशकों से आरक्षण की बहस कोटा बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन उनके न्यायसंगत वितरण की दिशा में पर्याप्त पहल नहीं हो पायी है। निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे, अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक–सामाजिक स्थिति वाले वर्ग ने ही बार–बार शिक्षा और सरकारी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों के भंवर–जाल में फंसे परिवार– मसलन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर परिवार लगातार हाशिये पर ही बने हुए हैं। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य संरचनात्मक असंतुलन को ही ठीक करना है तो इसके लाभ सीमित दायरे के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग के लिये यह प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसमें दो राय नहीं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आरक्षण लाभ में इस तरह के एकाधिकार को रोकने का एक सशक्त साधन है। इस प्रावधान का वंचित अनुसूचित जातियों तक विस्तार करना एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है कि सामाजिक गतिशीलता, हालांकि सीमित स्तर पर कुछ ही लोगों के लिये संभव हुई है। साथ ही अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये नीति को अनुकूलित किया जाना वक्त की जरूरत है। वास्तव में वर्तमान स्थिति आरक्षण के न्यायसंगत लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने में तार्किक नजर नहीं आती। जब किसी आईएएस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का बच्चा सामाजिक रूप से हाशिये पर गए वर्ग के किसी व्यक्ति के मुकाबले समान लाभों का दावा करना जारी रखता है तो इससे लक्षित उद्देश्य कमजोर हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने पर उनके जातिगत भेदभाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह केवल यही दर्शाता है कि किसी भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह के भीतर, वंचितता की स्थिति अलग–अलग होती है। ऐसी अवस्था में, सबसे निचले स्तर के लोग राज्य के संरक्षण पाने के लिये प्राथमिकता के हकदार हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट मानदंड, सामाजिक पिछड़ेपन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये कारगर सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की टिप्पणी इस बात की ही परिचायक है कि सामाजिक न्याय का विस्तार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को सोच–समझकर बाहर करने से समानता के संवैधानिक वायदे की पुष्टि हो सकती है। इस पहल के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है, तो पहले इससे लाभान्वित लोगों को सुरक्षा कवच न मिल सकेगा। उनका तर्क हो सकता है कि कई बार आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंच जाने के बावजूद किसी भेदभाव व उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। निस्संदेह, इस कथन की तार्किकता विचारणीय है। लेकिन इसका एक निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि सामाजिक विसंगति और आर्थिक विषमता दूर करने का एकमात्र साधन आरक्षण ही नहीं हो सकता है। यहां यह भी विचारणीय होना चाहिए कि कई पीढ़ियों से आरक्षण लाभ पा चुके लोग, स्वेच्छा से उसका परित्याग करें तो इस दिशा में धनात्मक वातावरण बन सकता है। निश्चित रूप से ऐसे कदमों से मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की सकारात्मक पहल को संबल मिल सकेगा।

# राहुल गांधी से इतना क्यों डरती है भाजपा और सरकार?

अनिल जैन

वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि वे राहुल गांधी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। मगर होता यह है कि राहुल गांधी जब भी भाजपा और उसकी सरकार, खास कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उनके उद्योगपति मित्रों को लेकर कोई सवाल उठाते हैं या गंभीर आरोप लगाते हैं अथवा किसी बड़े संकट से सरकार को आगाह करते हैं या फिर चुनावी गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, तो उनका जवाब देने के लिए भाजपा के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री मैदान में उतर जाते हैं। वे राहुल की बातों या उनके आरोपों का कोई तर्कसंगत जवाब देने के बजाय कभी उन्हें पागल, पप्पू, मूर्ख आदि विशेषणों से नवाजते हैं या उन्हें देशद्रोही, कभी चीन और जॉर्ज सोरोस का एजेंट तो कभी आतंकवादी तक करार देने लगते हैं। भाजपा नेताओं के इस अभियान में उसके प्रचारतंत्र का हिस्सा बन चुके कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया के साथ ही रिटायर हो चुके कुछ पत्रकार और संपादक भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक शामिल हो जाते हैं। कुछ मौकों पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर जजों, पूर्व नौकरशाहों व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों के समूह को तक भाजपा राहुल के खिलाफ मैदान में उतार देती है। ऐसे सेवानिवृत्त जजों और नौकरशाहों में कुछ तो ऐसे होते हैं, जिन पर उनके सेवाकाल में लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच चल रही होती है और कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि वाले होते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया में भाजपा ईकोसिस्टम भी पूरी सक्रियता से राहुल गांधी के चरित्र हनन में जुट जाता है।

बात यहीं नहीं रुकती। राहुल गांधी के बयानों को लेकर उनके खिलाफ भाजपा शासित राज्यों में मुकदमे भी दर्ज करा दिए जाते हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए संगीन से संगीन अपराध की एफआईआर दर्ज कराना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन राहुल के खिलाफ शिकायत चंद मिनटों में दर्ज हो जाती है। इतना ही नहीं, कुछ ही दिनों बाद उस एफआईआर के आधार पर निचली अदालत राहुल को समन भी जारी कर देती है। इस समय राहुल गांधी देश में अकेले ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ भावनाएं आहत करने के करीब 400 मुकदमे देश भर में दर्ज हैं। राहुल के बयानों को लेकर इस बहुआयामी कवायद में भाजपा की बौखलाहट और डर साफ नजर आता है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के समय राहुल द्वारा दी गई चेतावनियों को लेकर भी भाजपा ने ऐसा ही किया था। पिछले दिनों पश्चिम एशिया में शुरू हुए युद्ध को लेकर जब राहुल ने भारत में भी ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी की चेतावनी दी, तो भाजपा नेताओं और मीडिया ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। खुद मोदी ने पांच राज्यों में अपनी चुनावी रैलियों में राहुल की चेतावनी को खारिज करते हुए उन पर लोगों को डराने का आरोप लगाया। मगर चुनाव खत्म होते ही खुद मोदी ने मान लिया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते दुनिया भर में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है, जो समूची अर्थव्यवस्था को गहरे तक प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में लोगों से पेट्रोल–डीजल, रसोई गैस, खाद तेल, रासायनिक खाद आदि के इस्तेमाल में कटौती करने और कम से कम एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील भी की। इस समय भी राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर पूरी केंद्र सरकार, भाजपा और मीडिया के निशाने पर हैं। राहुल ने अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक स्तर पर बिगड़ते आर्थिक हालात से भारत भी अछूता नहीं है, जिसके चलते तेजी से बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से लोगों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसका असर देश की राजनीति पर भी जल्द ही दिखाई देगा और मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल के इस बयान में भाजपा अपनी सरकार के खिलाफ साजिश सूंघ रही है और उसके तमाम बड़े–छोटे नेताओं के नथूने फड़फड़ा रहे हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा के प्रवक्ता, टीवी चौनलों के एंकर और भाजपा समर्थक राजनीतिक विश्लेषक राहुल गांधी के इस बयान पर बुरी तरह उबलते हुए कह रहे हैं कि राहुल का यह बयान एक निर्वाचित सरकार और देश को अस्थिर करने की खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। राहुल के बयान पर यह प्रतिक्रिया बताती है कि भाजपा और उसकी सरकार का शीर्ष नेतृत्व हर मोर्चे पर अपनी नाकामी से उपज रहे व्यापक जन–असंतोष से बुरी तरह घबराया हुआ है और वह राष्ट्रवाद व देशभक्ति की दुहाई देते हुए उस असंतोष का दमन करने का इरादा रखता है। सेमुअल जानसन ने दो सौ साल पहले ठीक ही कहा था–देशभक्ति, दुष्टों की अंतिम शरणस्थली होती है। राहुल की भविष्यवाणी में कितना दम है, यह एक अलग बात है लेकिन बहरहाल देश में मूर्खता और मक्कारी के अंतिम पायदान पर खड़े इन भाजपा नेताओं, टीवी चौनलों के एंकरों और सत्ता के दलाल कथित राजनीतिक विश्लेषकों को यह बताना लाजिमी है कि राहुल गांधी देश में पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की है। उनसे पहले भी कई मौकों पर विपक्षी नेताओं ने अपने समय की निर्वाचित सरकारों के गिरने की भविष्यवाणियां की हैं। वे भविष्यवाणियां सही साबित भी हुईं लेकिन किसी ने विपक्षी नेताओं को देशद्रोही नहीं कहा या उन्हें देश को अस्थिर करने की साजिश में शामिल नहीं बताया। इस सिलसिले में सबसे पहला वाकया 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार के समय का है। उस सरकार के बनने के कुछ समय बाद जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सिर–फुटौव्वल शुरू हो गई थी। तब इंदिरा गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता आए दिन कहते थे कि यह सरकार जल्दी ही गिर जाएगी और वह सरकार ढाई साल में गिर भी गई थी।

# मोदी सरकार में बच्चों का भविष्य खतरे में!

नरेन्द्र मोदी के हिंदू–मुस्लिम एजेंडे को धर्म की रक्षा मानना और हिंदू जाग गया है जैसे बेतुके दावों पर यकीन करके इस देश ने किस तरह अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है, उसका ताजा उदाहरण सीबीएसई के बारहवीं परीक्षा के नतीजे हैं। भारत जैसे देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है, जिसमें विद्यार्थियों की योग्यता का पैमाना परीक्षाओं में हासिल किए अंक ही होते हैं। तीन घंटे का एक प्रश्नपत्र कोई छात्र कैसे हल करता है और कितने अंक हासिल करता है, वही उसका भविष्य तय करता है। इसमें उसकी बाकी काबिलियत, साल भर की मेहनत, किसी सवाल को अलग तरह से देखने का नजरिया यह सब बेमानी हो जाता है। ऐसी व्यवस्था में बारहवीं कक्षा के परिणाम कितने अहम होते हैं, यह सब जानते हैं। कायदे से तो इस पूरी घिसी–पिटी व्यवस्था को ही दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि नयी पीढ़ी दुनिया में अपना स्थान बना पाए। लेकिन मोदी सरकार ने तो इस व्यवस्था को और बर्बाद करने का काम किया है। पाठक जानते हैं कि इस साल मूल्यांकन प्रणाली को त्रुटिरहित बनाने और परीक्षा परिणाम जल्द घोषित करने के नाम पर ऑनस्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक कृष्ण कुमार जैसे कुछ शिक्षाविदों व जानकारों ने तब भी आशंका जताई थी कि ओएसएम को बिना जांचे–परखे, जल्दबाजी में अपनाया गया है। लेकिन सीबीएसई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब परिणाम आए तो बहुत से बच्चों ने निराशा जताई कि उन्हें उम्मीद के अनुरूप अंक नहीं मिले, इसलिए उन्होंने ओएसएम को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन बीते दो दिनों में तो एक ऐसी गड़बड़ी सामने आई जिसके बाद सवाल उठते हैं कि क्या सीबीएसई पर क्या कोई गिरोह हावी है, जो बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर मुनाफा कमा रहा है। दरअसल वेदांत नाम के एक बच्चे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फिजिक्स की जो उत्तरपुस्तिका उसकी बताई गई है, वह दरअसल उसकी है ही नहीं। उसके अक्षर और सीबीएसई की तरफ से दी गई उत्तरपुस्तिका में लिखे गए अक्षर बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। वेदांत की शिकायत सामने आने पर एबीपी न्यूज की पत्रकार अजातिका सिंह ने उसके घर जाकर बातचीत की, जिसमें वेदांत ने अपनी तरफ से सबूत भी दिखाए कि वह किस तरह उत्तर लिखता है और इसमें कितने अलग तरीके से उत्तर दिए गए हैं। एक पत्रकार ने अपना कर्तव्य निभाया और मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। लेकिन इससे पहले डीडी न्यूज के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने वेदांत की पोस्ट पर लिखा कि श्क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम्स दिए हैं?श दरअसल वेदांत की लोकेशन साउथ एशिया बताई गई तो दूरदर्शन के पत्रकार ने उसे सीधे पाकिस्तानी कह दिया। भाजपा समर्थक कई और लोगों ने वेदांत को जॉर्ज सोरोस के लिए काम करने वाला, पाकिस्तानी, देशद्रोही और न जाने क्या–क्या कहा। भारतीय समाज नफरती राजनीति से ग्रस्त होकर मानसिक तौर पर कितना बीमार हो चुका है, यह उसका नायाब उदाहरण है। साउथ एशिया में ही भारत भी आता है, लेकिन चूंकि वेदांत की शिकायत से सीबीएसई और अंततरू मोदी सरकार की पोल खुल रही थी, इसलिए एक 17 साल के बच्चे की ट्रोलिंग में पढ़े–लिखे लोगों को हिचक नहीं हुई। वेदांत के अभिभावकों की पीढ़ी के तमाम लोगों के लिए यह गंभीर चेतावनी है कि उन्हें कितना सोच–समझकर वोट देना चाहिए। अगर वे मंदिर–मस्जिद के नाम पर वोट देते हैं, तो तय मानिए कि नफरत का अगला शिकार उनकी अपनी संतान होगी। बहरहाल, वेदांत के समर्थन में समाज में बड़े पैमाने पर लोगों ने आवाज उठाई, एक वकील ने उसके लिए केस तक लड़ने का प्रस्ताव दिया, इसके बाद अशोक श्रीवास्तव ने अपना ट्वीट डिलीट किया और किंतु–परंतु के साथ अफसोस जाहिर किया। हालांकि इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि आईंदा किसी और मासूम को सही शिकायत पर ऐसे ट्रोल नहीं किया जाएगा। इस सरकार में निर्दोष को कटघरे में खड़ा करना ही सबसे आसान काम हो गया है। वेदांत मामले में राहत इस बात की है कि सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली है और सोमवार रात ट्वीट किया कि श्डियर वेदांत, फिजिक्स आंसर शीट को लेकर जो आपकी चिंता थी उस पर हमारा ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। समीक्षा के बाद मामले की जांच कर ली गई है और आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर भेज दी गई है। साथ ही, आवश्यकता अनुसार आपके परिणाम को अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको अपने निरंतर सहयोग का आश्वासन देते हैं।

# लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और वर्तमान पत्रकारिता की साख', (पत्रकारिता दिवस विशेष)

मुक्त गगन का सिंहनाद है, जो सोतों को जगा रही,
कलम नहीं यह महावज्र है, जो तिमिर चीरती जा रही।

भारतीय वांग्मय में श्शब्दश को ब्रह्म कहा गया है। शब्द जब लोक–कल्याण की उदात्त भावना से ओतप्रोत होकर अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है, तब पत्रकारिता का जन्म होता है। ३० मई १८२६ को जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने श्उदन्त मार्तण्डश का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी, तब उनका ध्येय केवल सूचनाओं का आदान–प्रदान नहीं, बल्कि सुषुप्त राष्ट्र की चेतना को झकझोरना था। पत्रकारिता मूलतः जन–आकांक्षाओं का दर्पण और व्यवस्था के गलियारों में गूँजती आम जनता की निर्भीक आवाज है। इसे लोकतंत्र का श्चौथा आधार स्तंभश इसलिए माना गया है क्योंकि जब

कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अपनी व्यावहारिक सीमाएँ होती हैं, तब पत्रकारिता समाज के सजग प्रहरी के रूप में संतुलन बनाने का कार्य करती है।

आज के दौर में पत्रकारिता के मायनेरू

आज इक्कीसवीं सदी के तकनीकी युग में पत्रकारिता के मायने और उसका स्वरूप तेजी से बदला है। सूचनाओं का प्रवाह अब क्षणिक और अबाध है; श्ब्रेकिंग न्यूजश की अंधी दौड़ और पल–पल बदलते डिजिटल एल्गोरिदम ने खबरों की गति तो बढ़ा दी है, लेकिन उनकी गहराई को आंशिक रूप से प्रभावित किया है। आज के दौर में पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि यह व्यावसायिक हितों, वैचारिक एजेंडों और सनसनीखेज विमर्श के कोलाहल के बीच दबे श्सत्यश को खोज निकालने का एक अत्यंत गंभीर दायित्व बन गई है। वर्तमान युग में इसकी सार्थकता इस बात में है कि वह किसी भी प्रभाव से मुक्त रहकर जनहित के प्रतिपक्ष के रूप में अडिग खड़ी रहे।

श्क्या पत्रकारिता को मिल पा रहा है वास्तविक अर्थ?

यह प्रश्न आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और आत्ममंथन की माँग करने वाला है। क्या वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता को वह मूल अर्थ और गरिमा पूरी तरह मिल पा रही है, जिसके लिए पूर्ववर्ती मनीषियों ने अपनी कलम को राष्ट्र–निर्माण का शस्त्र बनाया था? पत्रकारिता का वास्तविक अर्थ हैकृश्निष्पक्षता, निर्भीकता और जन–सरोकारश। परंतु वर्तमान में यह स्तंभ व्यावसायिकता और ध्रुवीकरण के भारी दबाव तले दबता दिख रहा है। खबरों को अक्सर पक्षों में बांटकर देखा जाने लगा है, जिससे जो शुद्ध और तटस्थ सत्य है, वह कहीं ओझल हो जाता है। जब सूचनाएँ केवल एक उत्पाद बनने लगें, तब पत्रकारिता अपने वास्तविक अर्थ से भटकने लगती है। शोर को विमर्श का विकल्प मान लेना इस विधा के मूल स्वरूप का अवमूल्यन है।

सजकता और सक्रियतारू चौथे स्तंभ की जीवंतता का मार्ग

इस चौथे स्तंभ को जीवित, प्राणवान और सफल बनाए रखने के लिए हमें अपनी नैतिक और वैचारिक सक्रियता को पुनः जाग्रत करना होगा। इसके लिए कुछ मौलिक और व्यावहारिक कदम आवश्यक हैं:

वैचारिक स्वतंत्रता और निष्पक्षतारू पत्रकारों को किसी भी तात्कालिक पूर्वाग्रह या विचारधारा का बंधक बनने से बचना होगा।

मौन बैठना महापाप है, तटस्थता जघन्य अपराध है,
सत्य पक्ष में जो न उठी, वह कलम नहीं निष्प्राण है।

पत्रकारिता में तटस्थता का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि बिना किसी भय या पक्षपात के केवल न्याय और सत्य के पक्ष में खड़े होना है।

संपादकीय अनुभव की कसौटी और आत्म–नियंत्रण रू विगत कई वर्षों से निरंतर संपादकीय लेखन के मेरे अपने व्यावहारिक अनुभव ने मुझे यह सिखाया है कि एक संपादक की कलम पर पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। संपादकीय लिखते समय सबसे बड़ी चुनौती और विशेष ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि हम अपनी व्यक्तिगत पसंद–नापसंद, तात्कालिक आवेश या किसी भी प्रकार के आंतरिक–बाहरी दबाव से पूरी तरह मुक्त रहें। शब्दों का चयन ऐसा हो जो समाज में बिखराव के बजाय वैचारिक परिपक्वता लाए। तथ्यों की कसौटी पर सौ बार परखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचना एक संपादक का परम धर्म है, क्योंकि हमारी लिखी एक–एक पंक्ति समाज की सोच की दिशा तय करती है।

मूल्यों और उत्तरदायित्व की पुनर्स्थापनारू समाचार संगठनों को लोक–कल्याण और व्यावसायिक स्थिरता के बीच एक विवेकपूर्ण संतुलन बनाना होगा। यदि विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी, तो इस स्तंभ की नींव कमजोर होने लगेगी। सत्यता की पुष्टि और गंभीर खोजी पत्रकारिता को प्राथमिकता देना ही इसकी सार्थकता है।

पाठकों का सजग दृष्टिकोणरू एक जागरूक समाज ही स्वस्थ मीडिया को जीवित रख सकता है। पाठकों और दर्शकों को भी सनसनीखेज खबरों के बजाय विचारोत्तेजक, प्रामाणिक और विकासात्मक पत्रकारिता को सराहना होगा।

अंततः, मैं यही कहना चाहूँगी... कि

लोकतंत्र के इस चौथे आधार स्तंभ को यदि अक्षुण्ण, दीर्घायु और प्रासंगिक रखना है, तो हमें कलम की मर्यादा और शब्द की शक्ति को पुनः स्थापित करना होगा। पत्रकारिता को किसी अंध–विरोध या अंध–समर्थन का साधन बनने के बजाय केवल और केवल लोक–चेतना का संवाहक बनना होगा। जब तक कलम की स्याही में समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का संकल्प और एक संपादक का आत्म–विवेक घुला रहेगा, तब तक लोकतंत्र का यह स्तंभ अपनी पूरी भव्यता के साथ अडिग खड़ा रहेगा।

डॉ संगीता मनीष बनाफर प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदी परिषद नई दिल्ली भारत छत्तीसगढ़ बिलासपुर

## तालाब की परंपरा–और हम

–समाज शेखर–

नदियों के बाद धरती की प्यास,
तालाबों से ही बुझती थी खास।
जीव–जंतु, पशु–पक्षी सारे,
इसी जल से जीवन पाते थे प्यारे।

किसान का खेत, तालाब के सहारे,
वर्षा रुके तो यही रखवाले।
पर अब आधुनिकता की होड़ में,
हम भूल गए तालाब के तोड़ में।

छह लाख गांव इस भारत में,
डेढ़ लाख प्यासे आज भी हैं।
बहत्तर फीसदी छोटे किसान,
बिन पानी सूखे खेत निहारें।

नहरें सूखीं, देखभाल नहीं,
पहाड़ों में नल की आस नहीं।
पर पुरखे जानते थे ये भेद,
बिन तालाब के कैसा खेद।

राम के युग का श्रृंगवेरपुर,
सातवीं सदी ईसा से पूर्व।
बी. बी. लाल ने खोज निकाला,
इलाहाबाद से दूर वो उजाला।

कुरुक्षेत्र का ब्रह्मसर बोलता,
कर्ण की झील आज भी डोलता।
हस्तिनापुर का शुकताल कहे,
महाभारत के जल की गाथा ये।

पांचवीं सदी से पंद्रहवीं तक,
तालाब ही तालाब खुदते थे तब।
रीवा में पांच हजार थे भाई,
मद्रास में तिरेपन हजार खुदाई।

मैसूर में उनतालीस हजार,
दिल्ली में साढ़े तीन सौ थे यार।
अंग्रेज आए, सब मिटने लगे,
तालाब की जगह मॉल बनने लगे।

राजा भोज का भोपाल ताल,
तीन सौ पैंसठ नदियों का जाल।
होशंगशाह ने जब तुड़वाया,
तीन बरस पानी बहता आया।
तीस साल दलदल सूख न पाया,
फिर खेत बना, अन्न उपजाया।

घड़सीसर जैसलमेर की शान,
एक सौ बीस मील जल की खान।
गोला ताल जयपुर के पास,
जयबाण तोप से जन्मा खास।

आबू का लखी सरोवर देखो,
नाखूनों से देव–ऋषि ने सींचो।
गोंडों का कूड़न हजार साल से,
आज भी देता जल बेमिसाल से।

दुर्गावती रानी ने भर दिए,
तालाबों से अपने राज्य जिए।
बरुआ सागर, अर्जुन सागर,
आज भी करते खेत उजागर।

बंगाल के पोखर, मछली के घर,
अब वो भी सूखे, दुख भरा डगर।

कभी देश में होड़ लगी थी,
तालाब बनाने की लगन लगी थी।
बुनई जगह चुनते, गुजरात नापते,
सिलवट पत्थर, सिरसाथ जल भांपते।

जलसूभा लकड़ी से पानी तोले,
खती काटे, सोनकर खोले।
मटकूट कूटे, चुनकर जोड़े,
दुग्गी, गोंड, धीमर, भोई मोड़े।

नोनिया, कोल, परमान, लुनिया,
मुरहा, झासी – कारीगर दुनिया।
पर अब सरकारें भूल गईं,
तालाब पाटने की सूली गईं।

ट्यूबवेल, हैंडपंप का शोर है,
पर तालाब का कोई ठौर है?
जल स्रोत सूखे, धरती प्यासी,
कब जागेगी जनता–सरकार आभासी?

जागो एक बार, मिलकर साथी,
तालाब बनाओ, मिटे दुख–राती।
पानी होगा तो जीवन होगा,
धरती का फिर से यौवन होगा।

मत्स्यपुराण का वचन सुनो,
दस कुओं पर बावड़ी गुनो।
दस बावड़ी का एक तालाब,
दस तालाब का पुत्र जनाब।

दस पुत्रों पर एक वृक्ष भार
तालाब बचाओ, यही समझदारी।

# पूजा भट्ट ने किया पैरेंट्स के रिश्तों पर खुलासा, किया उस रात का जिक्र जब महेश भट्ट बोले- मैं घर छोड़कर जा रहा

अभिनेत्री पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट और सोनी राजदान के रिश्ते से जुड़ी एक याद साझा की। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह उनके पिता ने उन्हें सोनी से प्यार होने के बारे में अवगत कराया था। जबकि तब दुनिया में किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने पिता के रिश्तों पर बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कुन्नूर में उनकी और सोनी की मुलाकात हुई थी। उस किस्से को याद करते हुए पूजा ने कहा, श्सोनी बोलीं कि पूजा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उन्हें पूरे दिल से कहा कि सोनी, आप एक मजबूत रिश्ते को तोड़ नहीं सकती थीं। एक मजबूत रिश्ते में किसी और के लिए कोई जगह नहीं होती, जब तक कि उसमें कोई दरार न हो या कोई कमी न हो, ताकि कोई और आकर उस कमी को पूरा कर सके। पूजा ने आगे यह भी बताया कि उनकी मां किरण भट्ट और पिता महेश भट्ट ने एक दूसरे के साथ हमेशा मर्यादा और शालीनता बनाए रखी। महेश भट्ट और सोनी राजदान के रिश्ते के बाके में बात करते हुए पूजा ने कहा, दरअसल, मुझे सोनी के बारे में मेरी मां से पहले ही पता चल गया था। उसने मुझे जगाया और कहा, 'मुझे तुम्हें बताना है कि मैं एक महिला से मिला हूं और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे पूजा ने कहा कि वह अपने पिता से इस बात को सुनना पसंद करती न कि किसी फिल्मी पत्रिका के जरिए। महेश ने वैसा ही किया उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी पूजा भट्ट को इस बारे में बताया। फिल्ममेकर महेश भट्ट की पहली शादी किरण भट्ट से की थी। उनके दो बच्चे हैं बेटी पूजा और बेटा राहुल। बाद में फिल्म सारांश की शूटिंग के दौरान

> आगे पूजा ने कहा कि वह अपने पिता से इस बात को सुनना पसंद करती न कि किसी फिल्मी पत्रिका के जरिए। महेश ने वैसा ही किया उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी पूजा भट्ट को इस बारे में बताया। फिल्ममेकर महेश भट्ट की पहली शादी किरण भट्ट से की थी।

वह सोनी राजदान से मिले। बाद में कपल 20 अप्रैल 1986 शादी के बंधन नें बंध गया। इस शादी से भी महेश के दो बच्चे हैं। आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट।

## द केरल स्टोरी' के बाद अब एलियन थ्रिलर से तहलका मचाएंगे विपुल शाह

बॉक्स ऑफिस पर द केरल स्टोरी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले निडर प्रोड्यूसर–डायरेक्टर विपुल अमृतलाल शाह एक बार फिर इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने आ रहे हैं। लीक से हटकर सोचने वाले विपुल शाह अब अक्षय कुमार के साथ मिलकर भारत की पहली प्रीडेटर–एलियन थ्रिलर फिल्म समुक लेकर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन मेकर्स ने इसके स्केल को लेकर जो खुलासे किए हैं, उसने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। अपनी मोस्ट–अवेटीड फिल्म गवर्नर के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च पर विपुल शाह ने समुक पर से पर्दा उठाते हुए कहा, समुक' एक ऐसी फिल्म है जो सिनेमा के सारे स्थापित नियमों को तोड़ देगी। इंडिया में आज तक ऐसी प्रीडेटर–एलियन थ्रिलर फिल्म नहीं बनी है। इस मेगा–प्रोजेक्ट के लिए हमने हॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गजों से हाथ मिलाया है। हॉलीवुड की हर प्रीडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस हमारे एलियन क्रिएचर को डिजाइन कर रहे हैं, जबकि वेनम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले एक्टर–डायरेक्टर ल्यूक इसके एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करेंगे। अक्षय कुमार के साथ अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, अक्षय और मैंने हमेशा नए जॉनर में हाथ आजमाया है, लेकिन यह फिल्म बेहद अनोखी है। इसे इतने बड़े इंटरनेशनल स्केल पर बनाया जा रहा है जो भारतीय दर्शकों के लिए एकदम नया होगा। हमारी टीम की शर्त थी कि जब तक हमें वो परफेक्ट इंटरनेशनल स्केल नहीं मिलता, हम शूटिंग शुरू नहीं करेंगे। डायरेक्टर कनिष्क वर्मा ने हॉलीवुड टेक्नीशियनों के साथ मिलकर इस क्रिएचर को परफेक्ट बनाने के लिए खून–पसीना बहाया है, और अब हम स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के इस महा–कोलाब्रेशन से साफ है कि समुक' के जरिए विपुल शाह बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, विपुल अमृतलाल शाह के प्रोडक्शन में बनी फिल्म गवर्नर के ट्रेलर ने आते ही इंटरनेट पर धूम मचा दी है। यह फिल्म 1990 के दशक में भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकट की सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी को बड़े पर्दे पर ला रही है। ट्रेलर में नेशनल अवॉर्ड विनर मनोज बाजपेयी का बतौर गवर्नर एक ऐसा कड़क और दमदार अवतार देखने को मिल रहा है, जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म को चिन्मय मांडलेकर ने डायरेक्ट किया है, जबकि इसके को–प्रोड्यूसर आशिन ए. शाह हैं। दमदार डायलॉग्स से सजी इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और खुद विपुल शाह ने मिलकर तैयार की है। सोने पर सुहागा यह है कि फिल्म के गाने महान गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत अमित त्रिवेदी का है। यह धमाकेदार फिल्म 12 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है।

# शादी के चार साल बाद मां बनेंगी अनुष्का रंजन, आदित्य सील ने शेयर की तस्वीरें, कई सेलेब्स ने दी बधाई

बॉलीवुड के मशहूर कपल आदित्य सील और अनुष्का रंजन माता–पिता बनने वाले हैं। शादी के चार साल बाद आदित्य सील और अनुष्का रंजन के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर करके फैंस के साथ खुशखबरी शेयर की है। आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने आज इंस्टाग्राम पर मैटरनिटी शूट की कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ दोनों ने फैंस के साथ खास अंदज में इस खुशखबरी को शेयर किया है। इन तस्वीरों में दोनों काले रंग के कपड़ों में बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आदित्य की टी–शर्ट पर बाप लिखा दिखाई दे रहा है। वहीं अनुष्का रंजन ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई बेहद खूबसूरत लग रही हैं। दोनों की ये तस्वीरें उनके फैंस और सेलेब्स को बेहद पसंद आ रही हैं। कपल ने माता–पिता बनने की घोषणा करके सभी फैंस का दिल जीत लिया है। इस खुशखबरी पर कई सेलेब्स और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने अपनी इन शानदार तस्वीरों के साथ एक प्यारा सा संदेश भी लिखा है। आदित्य सील और अनुष्का रंजन ने लिखा, मैंने सौ साल इंतजार किया है, लेकिन तुम्हारे लिए दस लाख साल और इंतजार कर सकता हूं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य साबित होगा। जैसे ही कपल ने यह गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर की, बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया। अनन्या पांडे, मौनी रॉय, भूमि पेडनेकर, सोनाक्षी सिन्हा, वाणी कपूर और मनीष मल्होत्रा जैसे कई बड़े कलाकारों के अलावा फैंस ने भी सोशल मीडिया पर इस जोड़े को माता–पिता बनने की ढेरों शुभकामनाएं और प्यार दिया। आदित्य सील और अनुष्का रंजन की पहली मुलाकात अनुष्का के परिवार के एक फंक्शन में हुई थी। शुरुआत थोड़ी अजीब थी, लेकिन धीरे–धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। लगभग 4 साल तक एक–दूसरे को डेट करने के बाद, आदित्य ने पेरिस में अनुष्का के जन्मदिन पर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। दोनों ने 21 नवंबर, 2021 को मुंबई में धूमधाम से शादी की थी। आदित्य सील को हाल ही में अक्षय कुमार और तापसी पन्नू की फिल्म श्खेल खेल में में देखा गया था।

## पिता विलासराव देशमुख की जयंती पर रितेश देशमुख को मिला सम्मान

रितेश विलासराव देशमुख इन दिनों अपनी हालिया फिल्म 'राजा शिवाजी' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। फिल्म की शानदार थिएटर रन के बीच अभिनेता को हिंदी और मराठी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के गौरव को समर्पित इस खास मौके पर रितेश देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई प्रमुख मंत्रियों और आयुक्तों की मौजूदगी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मान को और भी खास बनाने वाली बात यह रही कि यह पुरस्कार उन्हें उनके दिवंगत पिता विलासराव देशमुख की जयंती के अवसर पर प्रदान किया गया। इस वजह से यह पल अभिनेता के लिए बेहद भावुक और यादगार बन गया। यह सम्मान रितेश विलासराव देशमुख द्वारा अपनी फिल्मों के माध्यम से महाराष्ट्र की संस्कृति, जड़ों और समृद्ध इतिहास को पहचान दिलाने के प्रयासों को भी सलाम करता है। उनकी कहानियां सिर्फ प्रभाव नहीं छोड़तीं, बल्कि दर्शकों के दिलों से गहराई से जुड़ती हैं। 'वेड' और 'लाई भारी' के बाद रितेश विलासराव देशमुख ने 'राजा शिवाजी' के जरिए एक बार फिर निर्देशन की कमान संभाली। यह ऐतिहासिक फिल्म राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली मराठी फिल्म बन चुकी है। फिल्म ने दुनियाभर में 114.8 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। भव्यता और ऐतिहासिक प्रस्तुति के अलावा, फिल्म ने दर्शकों के बीच महाराष्ट्र की विरासत और भारत के महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक कहानी को जीवंत कर खास पहचान बनाई है। इस हालिया सम्मान के बाद अब दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि रितेश विलासराव देशमुख आगे भी ऐसी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण कहानियां बड़े पर्दे पर लेकर आएंगे।

# सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर मलाइका अरोड़ा ने दिया करारा जवाब, कहा- 'दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं'

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर होने वाली ट्रोलिंग्स को कमेंट्स को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अब उन्होंने अपनी इनर हैप्पीनेस यानी अंदर की खुशी को संभालना सीख लिया है। जानिए एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मलाइका ने कहा, 'मैं अपनी खुशी को इस तरह बचाती हूं कि मुझे याद रहता है कि इंटरनेट पर बहुत शोर होता है, लेकिन हर बात समझदारी भरी नहीं होती। अगर आप अपनी शांति को लोगों की राय के भरोसे छोड़ देंगे, तो आप कभी अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अपनी सीमाएं बनानी सीख ली हैं। अब मैं अपने बारे में हर बात नहीं पढ़ती और न ही हर किसी की राय को दिल पर लेती हूं। मैं असली जिंदगी, अपने काम, अपने करीबियों और अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देती हूं। यही चीजें मुझे जमीन से जोड़े रखती हैं।' मलाइका का मानना है कि उम्र के साथ सोच भी बदलती है। उन्होंने आगे कहा 'अब मैं हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। मुझे समझ आ गया है कि जो लोग आलोचना करते हैं, वह उनके बारे में ज्यादा बताता है, न कि मेरे बारे में। मेरी खुशी अब इस बात में है कि मैं खुद को जानती हूं और उसी में खुश हूं।' उन्होंने यह भी माना कि पहले वह भी बाकी लोगों की तरह सोचती थीं कि कहीं वह ज्यादा बोल्ड, ज्यादा ओपन या ज्यादा अलग तो नहीं हैं। लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है कि यही उनकी ताकत है। मलाइका ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'आज मैं जैसी हूं, उसे बिना किसी माफी के अपनाती हूं। अब मुझे खुद को बदलकर दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं लगती। अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर मुझे अपने आप में ही सुकून मिलता है।'

## पास्ता बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान, स्वाद-स्वाद में आसानी से कम हो जाएगा वजन

बढे हुए वजन को कम करना एक बड़ा ही मुश्किल और थका देने वाला टास्क होता है। इसके लिए लोगों को स्पेशल डाइट फॉलो करनी पड़ती है। आमतौर पर लोग वजन कम करने के सफर के दौरान घर का बना खाना ही खाते हैं। लेकिन एक समय के बाद घर का बना खाना उबाऊ लगने लगता है और लोगों के पास इसे खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। अगर आप भी अपने रोज के खाने से ऊब चुके हैं और कुछ स्वस्थ और स्वादिष्ट खाने का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो आप पास्ता को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, पास्ता खाने से वजन बढ़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर सही ढंग से पास्ता का सेवन किया जाए तो ये वजन कम करने में मदद कर सकता है। आज हम आपको सेहतमंद पास्ता बनाने की टिप्स बताने जा रहे हैं, जो आपकी वजन कम करने के सफर को स्वादिष्ट बना देंगे।

सही पास्ता का करें चुनाव– सेहतमंद और वजन कम करने के लिए पास्ता का सेवन कर रहे हैं तो जरुरी है कि सही पास्ता का चुनाव किया जाए। आमतौर पर लोग मैदा से बना पास्ता बनाकर खाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ जाता है। मैदा से बने पास्ता की बजाय बाजरा, ज्वार और रागी से बने पास्ता को चुने। साबुत अनाज से बना पास्ता खाने में स्वादिष्ट होने के साथ कई जरुरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

सब्जियों का करें इस्तेमाल– वजन करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ पास्ता का सेवन करना आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए आप पास्ता में सब्जियों का इस्तेमाल करें। इससे पास्ता में स्वाद और पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी और आपके वजन पर भार भी नहीं बढ़ेगा। पास्ता में आप मकई, ब्रोकोली, तोरी, शिमला मिर्च, प्याज, जैतून और हालापिनोज जैसी सब्जियां डाल सकते हैं।

सही तेल का इस्तेमाल करना जरुरी– पास्ता बनाने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है। जैतून का तेल पास्ता को आंत में चिपकने से रोकता है। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

## कच्चे आम की खट्टी-मीठी चटनी बढ़ाएगी आपके खाने का स्वाद, नोट करें रेसिपी

गर्मियों का खास फल है आम, इसे फलों का राजा कहा जाता है। हमारे भारत में कच्चे आम से कई तरह की चीजें बनाई जाती है जैसे कि आम का मुरब्बा, आम का अचार और साथ ही साथ आम की खट्टी मीठी चटनी भी खूब भारत में बनाई जाती है। आज हम आपको आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के बारे में बताने वाले हैं। जिसे लोग परांठे के साथ खाना ज्यादा पसंद करते है। तो चलिए जानते है इसकी रेसिपी के बारे में।

सामग्री

कच्चा आम –1

मिर्च पाउडर– आधा चम्मच

शक्कर–10 चम्मच

हल्दी पाउडर– 1 छोटा चम्मच

जीरा – 1 चुटकी

सौंफ – 1 चम्मच

मेथी– 1 चुटकी

नमक –स्वादानुसार

घी – 2 चम्मच

बनाने की विधि

1 सबसे पहले आम को अच्छे से धोकर छील लें और इसके छोटे– छोटे टुकड़े करें।

2 फिर एक कड़ाही में घी डालें और इसमें जीरा, मेथी और सौंफ डाल दें।

3 इसके बाद घी में आम के टुकड़े डालकर मिक्स करें।

4 इसमें नमक, शक्कर, हल्ध्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दें।

5 फिर करीब आधा कप से थोड़ा कम पानी डाल दें।

6 ध्यान रहे जब तक आम गलने न लगे तब तक इसे पकाएं।

7 अब कड़ाही में चटनी को अच्छी तरह मिक्स कर दें।

8 लीजिए तैयार है आपकी खट्टी मीठी आम की चटनी।

9 आप इसे 15–20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं।

10 आम की चटनी रोटी और स्नैक्स के साथ सर्व करें।

## ऑयली स्किन के लिए बेस्ट हैं ये होममेड फेस स्क्रब, मिलेगा नेचुरल ग्लो

गर्मियों में सूरज की तेज किरणों से हमारी स्किन का टैन होना आम बात है। लेकिन टैन स्किन से छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होता है। ऐसे में बिना सनस्क्रीम के बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं ऑयली स्किन होने पर भी गर्मियों में काफी दिक्कत होती है। यदि आपकी स्किन भी ऑयली है तो यह आर्टिकल आपके लिए है। बता दें कि आप कुछ घरेलू टैन स्क्रब की मदद से अपनी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को दूर करने के साथ ही पिंपल्स से भी निजात पा सकती हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए ऑयली स्किन के लिए कुछ ऐसे होममेड फेस स्क्रब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी समस्या को चुटकियों में हल कर देंगे।

कॉफी का स्क्रब

कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी स्किन के लिए नेचुरली ग्लो लाने में मदद करता है। बता दें कि कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। साथ ही इसमें मौजूद कैफीन स्किन को सही से एक्सफोलिएट भी करता है। इसके लिए एक चम्मच कॉफी मे एक बड़ा चम्मच दही मिक्स करें। इसके बाद इससे अपने फेस की 2–3 मिनट तक मसाज करें। फिर इसे फेस पर 5 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। इस स्क्रब को आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकती हैं।

नींबू और चीनी का स्क्रब

नींबू और चीनी का स्क्रब ऑयली स्किन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। थोड़ी सी चीनी लेकर इसके नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद इसे अपने फेस पर हल्के हाथों से रगड़ें। करीब 15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें। इससे आपको ऑयली स्किन से जल्द ही छुटकारा मिलेगा और इसका इस्तेमाल टैन हटाने के लिए भी कर सकते हैं।

मसूर दाल का स्क्रब

आपकी स्किन से डेड सेल्स और गंदगी हटाने के लिए मसूर दाल का स्क्रब सबसे बेहतर है। इस स्क्रब को बनाने के लिए दो चम्मच मसूर दाल को पीस लें। इसे ज्यादा महीन न करें। फिर इसमें एक चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दही मिलाएं। इसके बाद इस स्क्रब को पूरे फेस पर हल्के हाथों से 2–3 मिनट तक स्क्रब करें। सप्ताह में एक बार इस स्क्रब का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा।

शहद और चावल के पाउडर का स्क्रब

यह होममेड स्क्रब न सिर्फ आपकी ऑयली स्किन के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे आपको नेचुरल ग्लो भी मिलता है। इस स्क्रब को बनाने के लिए चावल के पाउडर में शहद मिलाएं। फिर इसे अपने फेस पर स्क्रब करें। इसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दें। यह स्क्रब आपकी स्किन के लिए बेहद लाभकारी है।

ऑरेंज पील स्क्रब

संतरे के छिलकों में मौजूद कंपाउंड न सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, बल्कि स्किन की रंगत भी निखारते हैं। इसका एक्सफोलिएटिंग एक्शन सेंसिटिव स्किन के लिए भी सही है। इसका स्क्रब बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें और उसमें 1 बड़ा चम्मच शहद और एक चुटकी हल्दी डालें। इस पेस्ट से 3–4 मिनट तक चेहरे को स्क्रब करें और फिर पानी से धो लें। इस स्क्रब का इस्तेमाल हफ्ते में दो बार करें।

## इन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है दूध का सेवन, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए दूध काफी फायदेमंद होता है। वहीं दूध का इस्तेमाल कई तरह की मिठाइयां आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। बता दें कि दूध में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो शरीर को पोषण प्रदान करने के साथ ही कई गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। दूध में मैग्नीशियम और कैल्शियम मौजूद होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीना सभी के लिए फायदेमंद नहीं होता है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो दूध का सेवन कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बता दें कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं होती हैं, जिनमें अगर दूध का सेवन किया जाता है। तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ऐसे में किन लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यह जानना बेहद जरूरी है। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने जा रहे हैं कि कौन सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।

शरीर में सूजन होने पर

हेल्थ एक्सपर्टेस के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सूजन संबंधी समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे स्वास्थ्य अधिक बिगड़ने की संभावना होती है। बता दें कि दूध में सैचुरेटेड फैट बाया जाता है। सैचुरेटेड फैट शरीर में लिपि पॉलीसेकेराइड नामक इन्फ्लेमेटरी

अणुओं के अवशोषण बढ़ाने का कार्य करता है। जिससे सूजन की समस्या बढ़ सकती है। वहीं कई रिसर्चों में भी डेयरी प्रोडक्ट्स को सूजन को बढ़ाने और सूजन से जुड़ी समस्याएं बढ़ाने आदि के बारे में दिखाया गया है।

लिवर संबंधी समस्या

यदि कोई व्यक्ति लिवर संबंधी किसी समस्या जैसे फैटी लिवर आदि हो तो उसे भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में लिवर दूध को अच्छे से पचा नहीं पाता है। जिसके कारण लिवर में सूजन की समस्या होती है और फैट बढ़ता है। इसके अलावा आपको पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

पीसीओएस

पीसीओएस या हार्मोनल असंतुलन से जुड़ी अन्य समस्या होने पर दूध का सेवन व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि दूध के सेवन से एंड्रोजन और इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। जो महिलाएं पीसीओएस पीड़ित होती हैं और वह डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी शरीर में हार्मोन और इंसुलिन का लेवल प्रभावित होता है। वहीं अगर आप हार्मोन के असंतुलन से जूझ रही हैं। तब भी आपको दूध के सेवन से बचना चाहिए।

दूध से एलर्जी

बता दें कि कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है। ऐसे लोग जब भी दूध पीते हैं तो उनके शरीर में एलर्जी की समस्या होती है। दूध से होने वाली एलर्जी की इस समस्या को को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। इन लोगों को दूध में मौजूद चीनी को पचाने से समस्या होती है। ऐसे में दूध का सेवन करने से गैस, ब्लोटिंग और दस्त आदि की समस्या होने लगती है।

पेट खराब होने पर

यदि कोई व्यक्ति पेट संबंधी समस्या से परेशान है, उसे कब्ज, ब्लोटिंग और गैस आदि की समस्या है। तो ऐसे समय में दूध का सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस दौरान दूध का सेवन नहीं करना चाहिए।

## ज्यादा गर्मी से तनाव में रहते हैं बच्चे, जानिए उनकी सही देखभाल का तरीका

नोएडा के मेदांता अस्पताल में बच्चों की देखभाल विभाग की डायरेक्टर डॉ. शालिनी त्यागी ने माता–पिता को सलाह दी कि वे बढ़ती लू की स्थिति के बीच बच्चों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। उन्होंने चेतावनी दी कि खराब मौसम के दौरान बच्चों को डिहाइड्रेशन, गर्मी के तनाव और इससे जुड़े संक्रमणों का खतरा ज्यादा होता है। मौसम में होने वाला हर बदलाव बड़ों की तुलना में बच्चों पर ज्यादा असर डालता है।

दस्त और डिहाइड्रेशन से पीड़ित होते हैं बच्चे

बच्चों के स्वास्थ्य पर गर्मी के असर के बारे में एएनआई से बात करते हुए डॉ. त्यागी ने कहा, अगर आप देखें, तो बच्चों के शरीर का सतह क्षेत्र उनके वजन के हिसाब से ज्यादा होता है, जिसका मतलब है कि वे ज्यादा गर्मी सोखते हैं। इसके अलावा, उनका थर्मोरेगुलेशन सिस्टम (शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला तंत्र) बड़ों जितना विकसित नहीं होता। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि मौसमी गर्मी के कारण बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं पैदा हो रही हैं। गर्मी की वजह से बच्चे दस्त और डिहाइड्रेशन से पीड़ित होते हैं, और इस दौरान कुछ श्वसन संक्रमण भी बढ़ जाते हैं। हालाक उन्होंने बच्चों की बाहरी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के खिलाफ भी आगाह किया।

बच्चों का इस तरह रखें ध्यान

डॉक्टर ने कहा–मैं बच्चों से यह नहीं कहूंगी कि वे बस घर पर बैठे रहें और बाहर खेलने न जाएं, क्योंकि खेलना उनके स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा है यह बड़ों के लिए व्यायाम के बराबर है। एम्स और यूनिसेफ के विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें थोड़ी–थोड़ी देर में पानी या ओआरएस देते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) न हो। चिलचिलाती धूप में, खासकर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच, बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। उन्हें हल्के, सूती और ढीले कपड़े पहनाएं ताकि हवा आसानी से पास हो सके। बचों को चिप्स और मीठे पेय पदार्थों देने से बचें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं।

## संक्षिप्त

### इंग्लैंड पर जीत के बाद क्या बोलीं स्मृति मंधाना?

लंदन,एजेंसी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे का शानदार आगाज करते हुए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में मेजबान टीम को 38 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1–0 की बढ़त बना ली। बल्लेबाजी में यास्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स ने दमदार अर्धशतक लगाए, जबकि गेंदबाजी में डेब्यू कर रहीं नंदिनी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट झटके। हरमनप्रीत कौर की गैरमौजूदगी में कप्तानी कर रहीं स्मृति मंधाना के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही। वह मैच की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गईं। इसके बाद शेफाली भी सिर्फ दो रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। दो शुरुआती झटकों के बाद यास्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 126 रन की बेहतरीन साझेदारी की। यास्तिका ने 40 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं जेमिमा ने सिर्फ 40 गेंदों पर 69 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया। अंत में दीप्ति शर्मा ने 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर भारत का स्कोर 188 रन तक पहुंचाया। 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। ऐलिस कैप्सी सिर्फ छह रन बनाकर आउट हुईं, जबकि सोफिया डंकले 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। इसके बाद हीथर नाइट और एमी जोंस ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़े। एमी जोन्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 67 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें सहयोग नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। डेब्यू मैच खेल रहीं नंदिनी शर्मा ने चार ओवर में 34 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वहीं क्रांति गौड़ ने दो विकेट हासिल किए। श्रीचरणी और दीप्ति शर्मा को भी एक–एक सफलता मिली। मैच के बाद कप्तान स्मृति मंधाना ने टीम के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने खास तौर पर यास्तिका भाटिया की वापसी को जीत का सबसे बड़ा कारण बताया। मंधाना ने कहा, पावरप्ले में दो विकेट गंवाना सही नहीं था। जीत का श्रेय 8 महीने बाद वापसी करने वालीं यास्तिका को जाता है। वह मैच को इंग्लैंड की पहुंच से दूर ले गईं। उन्होंने जेमिमा रोड्रिग्स की भी तारीफ करते हुए कहा, जेमिमा ने एक बार फिर वही काम किया, जो वह हमेशा करती हैं। कप्तान ने डेब्यू स्टार नंदिनी शर्मा की भी सराहना की। उन्होंने कहा, नंदिनी के अंदर दमदार प्रदर्शन करने की आग है। उन्होंने कुछ अहम ओवर डाले और महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे की शानदार शुरुआत की है और अब उसकी नजरें सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी।

### रसोई तक पहुंची महंगाई की आंच, 13 फीसदी बढ़ गई खाद्य तेल की कीमतें

नई दिल्ली,एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों को हिलाकर रख देने वाली भू–राजनीतिक उथल–पुथल ने अब भारतीय रसोई के बजट पर सीधा हमला बोल दिया है। पेट्रोल–डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की मार से पहले से ही परेशान आम परिवारों के लिए खाद्य तेलों की यह नई तपिश एक बड़ा झटका है। इस साल फरवरी से अब तक अलग–अलग खाद्य तेलों की थोक कीमतों में करीब 13 फीसदी का उछाल आ चुका है। आइग्रेन इंडिया के संस्थापक राहुल चौहान का कहना है कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रांसपोर्टेशन, बीमा और ट्रांजिट लागत बहुत बढ़ गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से पाम तेल का आयात पहले के मुकाबले अब महंगा पड़ रहा है। चौहान का कहना है कि छोटी अवधि में इन ऊंचे भावों पर बाजार थोड़े समय के लिए रुक सकते हैं और कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। लेकिन, लंबी अवधि का आउटलुक बेहद मजबूत नजर आ रहा है। इंडोनेशिया का बायोफ्यूल के लिए 50 फीसदी पाम तेल मिलाने का कार्यक्रम सफल रहने पर पाम तेल के निर्यात में और गिरावट आएगी।ईंधन महंगा होने से किसानों की लागत एवं माल ढुलाई के खर्च में आगे और बढ़ोतरी होगी, जिससे लंबी अवधि में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी बनी रहने का अनुमान है। भारत खाद्य तेल जरूरतों का 60 फीसदी आयात करता है। घरेलू कीमतें सीधे तौर पर वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों, शिपिंग और फ्रेट कॉस्ट से प्रभावित होती हैं। पहले रूस–यूक्रेन संघर्ष ने सूरजमुखी तेल की आपूर्ति रोकी और अब ईरान तनाव ने वनस्पति तेल बाजारों को संकट में डाल दिया है। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ा सकती हैं नमकीन और बिस्कुट के दाम खाद्य तेल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पैकेज्ड स्नैक्स (नमकीन), बेकरी आइटम, फ्रोजन फूड्स और रेडी–टू–ईट उत्पादों में किया जाता है। खाद्य तेल की कीमतों में उछाल से एफएमसीजी कंपनियों के लिए कच्चे माल की इनपुट लागत बढ़ गईध्है। लगातार बढ़ रही इस इनपुट लागत का बोझ खुद उठाने के बाद एफएमसीजी कंपनियां आखिरकार अब इसे उपभोक्ताओं की जेब पर डाल रही हैं। मोदी नेचुरल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अक्षय मोदी के अनुसार, वैश्विक तनावों ने कमोडिटी बाजारों को हिला दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें न केवल तेल खरीद, बल्कि पैकेजिंग, प्लास्टिक और पेपर की लागत को भी बढ़ा रही हैं।

# मानसिक तनाव, असहयोग या फिर खराब नतीजे? तीन साल बाद राहें अलग होने की असली वजह क्या

नई दिल्ली,एजेंसी। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या से इस फ्रेंचाइजी के रिश्तों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या अगले सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं रहना चाहते और उन्होंने यह फैसला सीजन के बीच में ही टीम प्रबंधन को बता दिया था। बीच सीजन यानी आईपीएल 2026 के 44वें मैच और मुंबई के चेन्नई के खिलाफ इस सीजन दूसरे मैच के बाद हार्दिक अचानक टीम से गायब हो गए थे। न ही वह टीम के साथ यात्रा करते दिखे और न ही टीम के साथ डग आउट में दिखे थे। तब एमआई ने बताया था कि उनको चोट लगी है और इसी वजह से नहीं खेल रहे हैं। हालांकि, अब यह बात भी सामने आ रही है कि हार्दिक और एमआई के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक आईपीएल सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, हार्दिक लगातार दबाव और खराब नतीजों से काफी परेशान थे। वह मानसिक रूप से तनाव में थे और पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें पीठ में चोट भी लगी थी। प्लेऑफ की उम्मीद खत्म होते ही उन्होंने टीम प्रबंधन को बता दिया था कि वह आगे टीम के साथ नहीं रहेंगे। हार्दिक ने 2024 में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाली थी। हालांकि, कप्तानी परिवर्तन के बाद से उन्हें लगातार आलोचना और फैंस की हूटिंग का सामना करना पड़ा। सूत्र ने बताया, श्यह समझना जरूरी है कि हार्दिक अभी सिर्फ 32 साल के हैं। वह 2024 में 30 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस में लौटे थे। पहले ही सीजन में उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा और इस बार भी चीजें योजना के मुताबिक नहीं रहीं। यह बयान उस कप्तानी बदलाव के संदर्भ में आया, जिसमें बेहद लोकप्रिय रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था। पिछले दो सीजन में मुंबई इंडियंस के फैंस ने कई मैचों के दौरान हार्दिक पांड्या की लगातार हूटिंग की। हालांकि, इस दौरान वह इससे प्रभावित नजर आए, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि यह सफर मुश्किल जरूर रहा, लेकिन दिलचस्प भी था। आईपीएल

सूत्र के मुताबिक, अब हार्दिक का धैर्य जवाब दे चुका है। पिछले तीन सीजन में मुंबई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम पिछले सीजन प्लेऑफ में जरूर पहुंची, लेकिन क्वालिफायर–2 में पंजाब से हारकर बाहर हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक को उम्मीद थी कि टीम में सभी खिलाड़ी एक दिशा में काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्र ने बताया, मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम वैसा नहीं था, जैसा हार्दिक 2021 में छोड़कर गए थे। हर सीनियर खिलाड़ी एक राय पर नहीं था। अगर नतीजे अच्छे आते तो शायद निराशा इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब हर कोई अलग दिशा में सोचने लगे तो मानसिक दबाव बढ़ जाता है। इसी वजह से हार्दिक ने तय कर लिया था कि वह अगले सीजन में मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं होंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पांड्या को सबसे ज्यादा इस बात ने आहत किया कि जब वह भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेलते थे, तब सीनियर खिलाड़ी उनसे 100 प्रतिशत समर्पण की उम्मीद रखते थे, लेकिन जब वह फ्रेंचाइजी की कप्तानी कर रहे थे, तब उन्हें वैसा सहयोग और प्रतिबद्धता वापस नहीं मिली। फिलहाल यह साफ नहीं है कि हार्दिक किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के साथ ट्रेड करेंगे या फिर आईपीएल ऑक्शन में उतरेंगे। इस साल अगस्त तक इसको लेकर कुछ हद तक चीजें साफ हो सकेंगी। पर एक बात तय है कि हार्दिक अब मुंबई इंडियंस के साथ नहीं रहना चाहते। जिस सीनियर खिलाड़ी की यहां बात हो रही है, उसमें रोहित के अलावा सूर्यकुमार और बुमराह हो सकते हैं। हालांकि, सूत्र ने नाम का खुलासा नहीं किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर हार्दिक किसी नई टीम में जाना चाहते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। हालांकि, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर जरूर इस बात के कयास हैं कि सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ और आयुष म्हात्रे से हार्दिक को ट्रेड कर सकती है। चर्चाएं शिवम दुबे और म्हात्रे को लेकर भी हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर हार्दिक मुंबई इंडियंस छोड़ते हैं, तो टीम को नए कप्तान की तलाश करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रेंचाइजी के सामने दो विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प है कि अनुभवी रोहित शर्मा को एक बार फिर कप्तानी सौंपी जाए। रोहित ने मुंबई इंडियंस को पांच आईपीएल खिताब दिलाए हैं और वह अभी भी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हैं। दूसरा विकल्प युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को भविष्य के कप्तान के तौर पर तैयार करना हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई इंडियंस लंबे समय के लिए तिलक वर्मा पर भरोसा जता सकती है और नई टीम तैयार कर सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि आने वाले महीनों में हार्दिक पांड्या का अगला कदम क्या होगा।

# आईपीएल में स्मार्ट ग्लासेस पर सख्ती,बीसीसीआई ने क्यों लागू किए नए सुरक्षा नियम?

मुंबई,एजेंसी। एसीएसयू के मुताबिक, हाल के दिनों में कई टेक्नोलॉजी कंपनियां आईपीएल खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी स्टाफ को स्मार्ट सनग्लासेस और स्मार्ट गॉगल्स बेच रही थीं। देखने में ये सामान्य चश्मों जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें कई एडवांस फीचर्स मौजूद होते हैं। इन डिवाइस के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, टेक्स्ट मैसेज भेजना और प्राप्त करना, ऑडियो–वीडियो कॉल करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं संभव हैं। इसी वजह से एसीएसयू ने इन्हें कम्युनिकेशन और ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की श्रेणी में रखा है। नए नियमों के तहत मैच वाले दिन प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया में स्मार्ट ग्लासेस रखने या इस्तेमाल करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह प्रतिबंध ड्रेसिंग रूम, डगआउट और खिलाड़ियों के व्यूइंग एरिया समेत सभी हाई–सिक्योरिटी जोन में लागू रहेगा। एसीएसयू का मानना है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल रियल टाइम में जानकारी साझा करने या सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से इन्हें अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह माना जाएगा। नए दिशा–निर्देशों के अनुसार, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को स्टेडियम पहुंचते ही अपने स्मार्ट ग्लासेस सिक्योरिटी लायजन ऑफिसर (स्) के पास जमा कराने होंगे। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह इन्हें भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा। अगर कोई खिलाड़ी या स्टाफ सदस्य पीएमओए के अंदर स्मार्ट ग्लासेस के साथ पाया जाता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और व्यक्तिगत जुर्माना लगाया जा सकता है। आईपीएल 2026 के श्मिनिमम स्टैंडर्ड्सश नियमों के तहत सजा तय की जाएगी। आईपीएल 2026 में कुछ घटनाओं ने भी बीसीसीआई की चिंता बढ़ाई है। राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में ई–सिगरेट इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए थे।

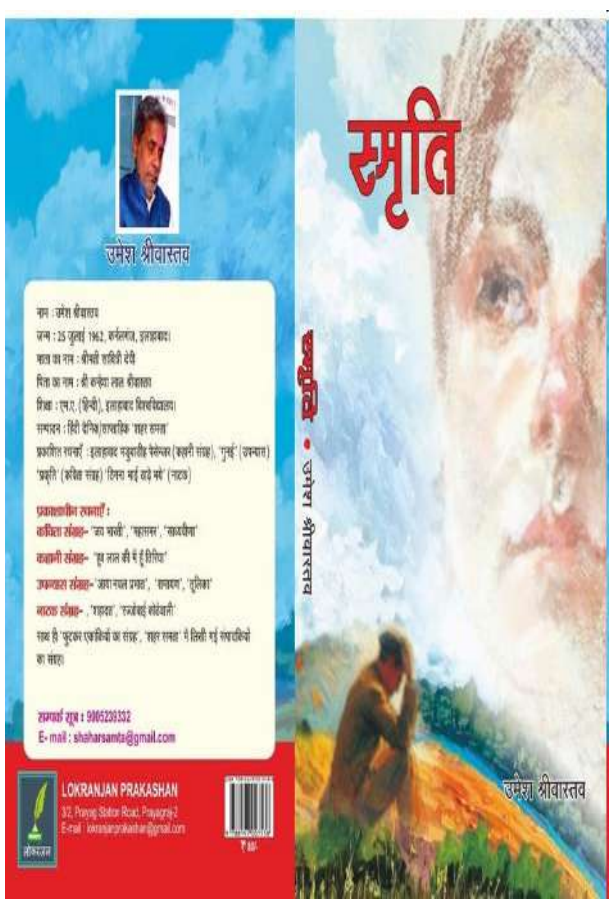


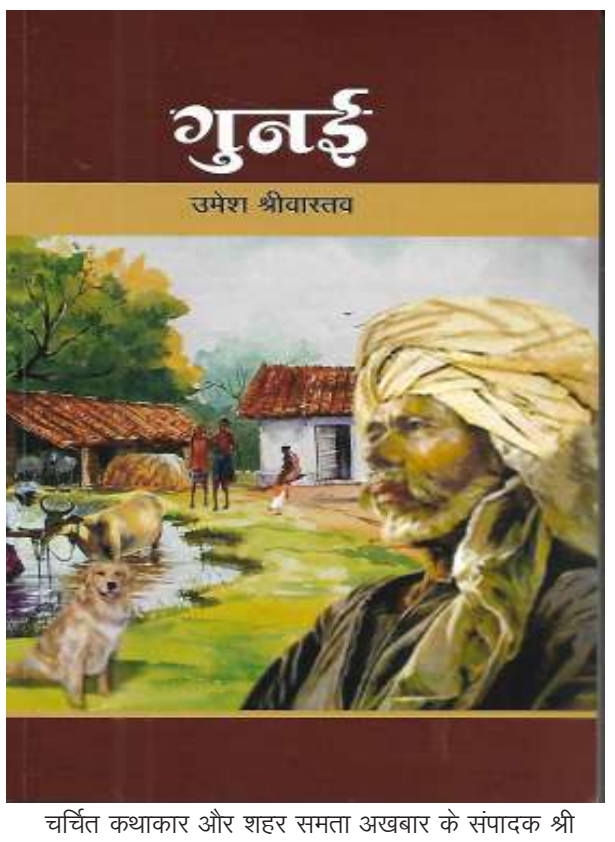


चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित

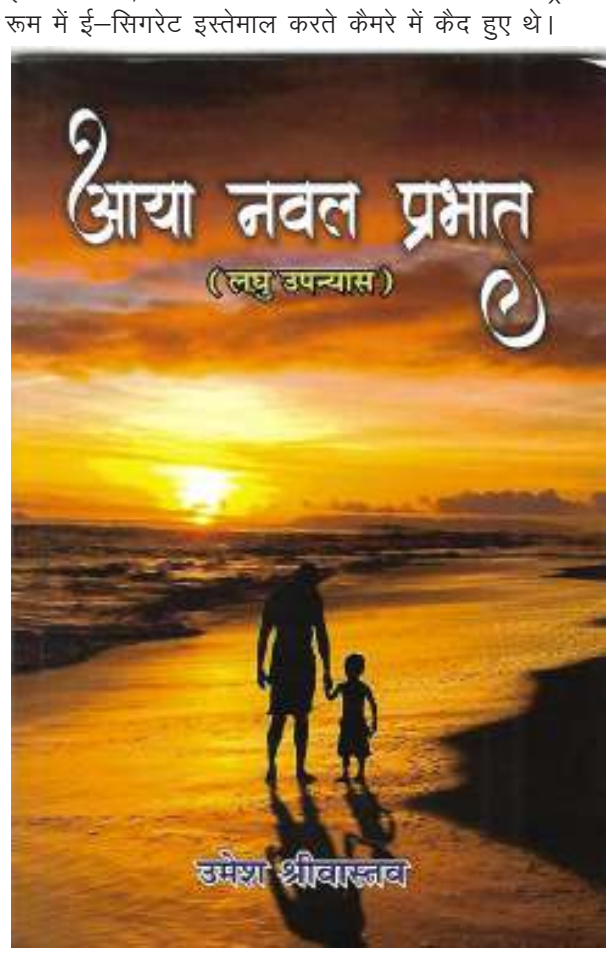


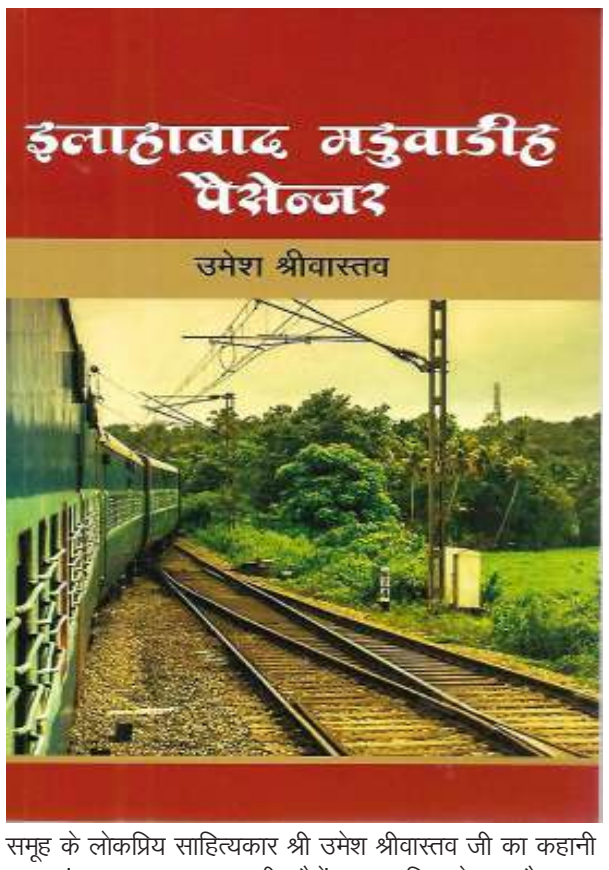


समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।

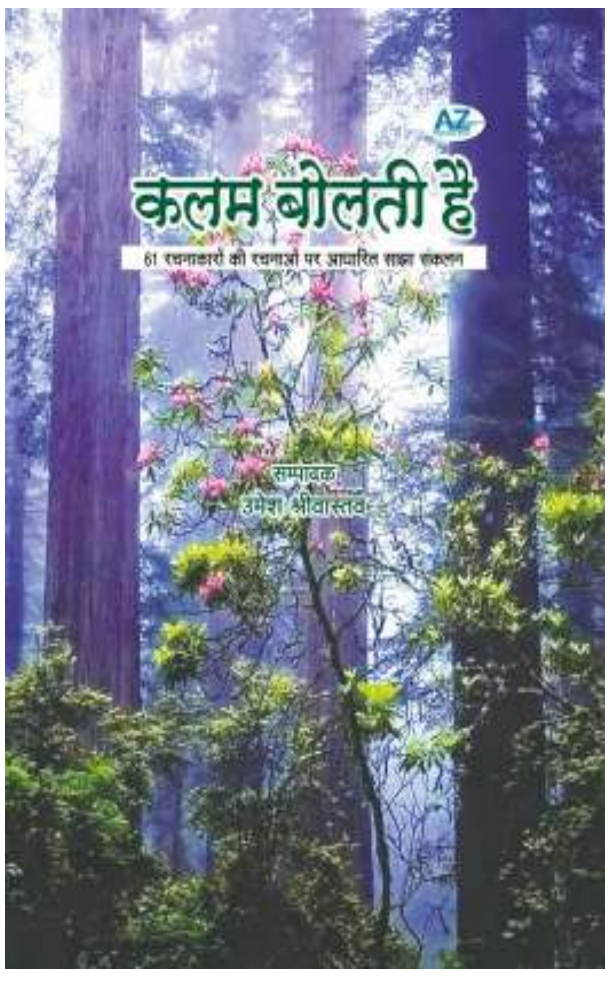


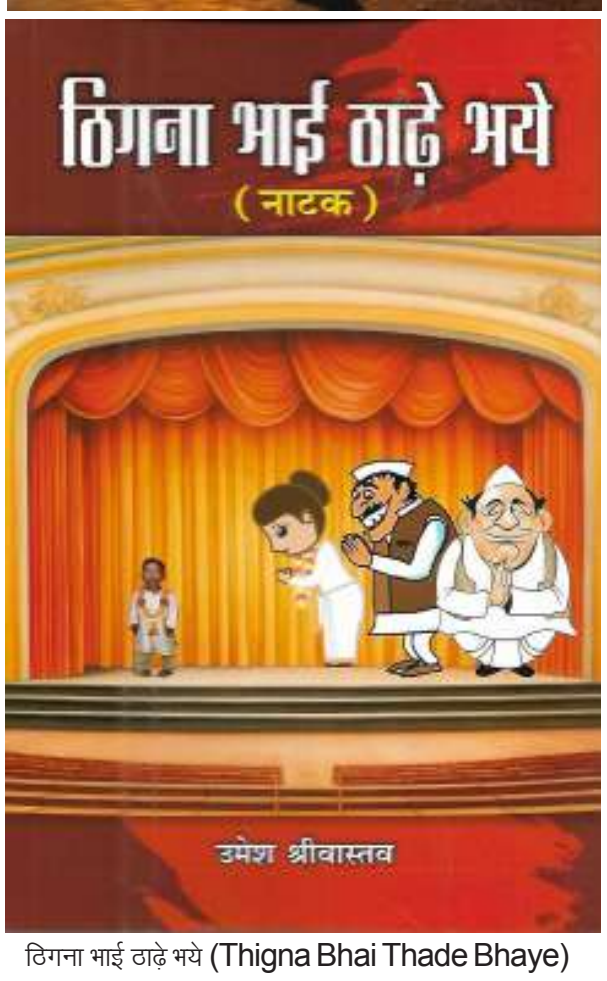


ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

शहर समता | विदेश | इलाहाबाद शनिवार, 30 मई 2026 | 8

## संक्षिप्त

### ‘हमारे लिए जबरदस्त प्यार, नेतन्याहू बोले- वैश्विक आलोचना के बावजूद भारत ने हमेशा इस्राइल का साथ दिया

यरूशलम,एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को एक महाशक्ति बताया। उन्होंने कहा है कि दुनिया




के कई हिस्सों में इस्राइल को आलोचनाओं और यहूदी राज्य की वैधता पर सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत में इस्राइल के प्रति लोगों का समर्थन और स्नेह बेहद मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्राइल के लिए अविश्वसनीय और जबरदस्त प्यार देखने को मिलता है। जॉर्डन वैली में गुरुवार को आयोजित एक नेतृत्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने भारत–इस्राइल संबंधों को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का अहम स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि इस्राइल अपने अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का लगातार विस्तार कर रहा है और इस दिशा में भारत के साथ उसका विशेष रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने गठबंधनों का विस्तार कर रहे हैं और इस बड़े दायरे में भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश के साथ हमारा अनूठा संबंध शामिल है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के अन्य हिस्सों में इस्राइल को लेकर आलोचनात्मक माहौल हो सकता है, लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है। अपने फॉलोअर्स के बारे में क्या बोले नेतन्याहू? उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि सोशल मीडिया पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारत से हैं। नेतन्याहू ने इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों और भारत–इस्राइल सहयोग की मजबूती का जिक्र किया है। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। नेतन्याहू की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं और इस्राइल अपने पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़कर नए वैश्विक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

### अगले 5 साल में रिकॉर्ड 1.5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, दुनिया को करना पड़ेगा खतरनाक मौसम का सामना

वॉशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र की नई जलवायु रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगले पांच वर्षों के दौरान पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान पृथ्वी के सबसे गर्म वर्ष का रिकॉर्ड भी कई बार टूट सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने यह भी अनुमान जताया है कि 2030 तक आर्कटिक क्षेत्र का तापमान करीब 1.66 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन क्षेत्र में गंभीर सूखे और वनाग्नि का खतरा भी बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोयला, तेल और गैस के इस्तेमाल से बढ़ रही वैश्विक गर्मी के कारण बाढ़, सूखा–भीषण गर्मी जैसी मौसमी घटनाएं अधिक होंगी। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु एजेंसी और ब्रिटेन के मौसम विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 से 2030 के बीच औसत वैश्विक तापमान के औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने की 75: आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक, तापमान में मामूली वृद्धि भी मौत, खतरे और जीव–जंतुओं की प्रजातियों को क्षति पहुंचाएगी। प्रवाल भित्तियों और ग्लेशियर जैसे कई प्राकृतिक तंत्र इस अतिरिक्त दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे। एजेंसी 1.5 डिग्री तापमान बढ़ेगा डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच वर्षों में कम से कम एक वर्ष के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की 91: आशंका है। वहीं, 2024 में बने पृथ्वी के सबसे गर्म वर्ष के रिकॉर्ड के टूटने की आशंका 86: बताई गई है। अनुमान है कि 2030 तक हर वर्ष का तापमान 19वीं सदी के अंत की तुलना में 1.3 से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। अल नीनो की संभावनारू कम अवधि के मौसम पूर्वानुमानों में अल नीनो की संभावना जताई गई है। डब्ल्यूएमओ ने कहा, इसका असर 2028 तक रहने से 2027 में 2024 का रिकॉर्ड टूट सकता है। तापमान रोकने के प्रयास नाकाफीरू संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टिल ने कहा, हाल के वर्षों में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के प्रयास नाकाम रहे हैं। दुनिया के लिए गंभीर रिपोर्ट की सह–लेखिका मेलिसा सीब्रुक ने कहा, 1.5 डिग्री सेल्सियस कोई ऐसी अंतिम सीमा नहीं है। लेकिन हर 0.1 डिग्री तापमान वृद्धि के साथ असर और गंभीर होता जाएगा। लंदन की जलवायु विज्ञानी फ्रेडरिक ओटो ने कहा, यदि पूरे वर्ष तक तापमान 1.5 डिग्री से ऊपर रहा, तो दुनिया को खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ेगा जो बेहद गंभीर होगा।

### बकरीद पर मातम: इस्राइली हमलों में 10 लोगों की मौत, नेतन्याहू ने गाजा पर 70 फीसदी नियंत्रण का किया एलान

गाजा सिटी, एजेंसी। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इस्राइली सेना ने गाजा पट्टी के 60 फीसदी हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस्राइल का अगला कदम गाजा के 70 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करना है और सेना हर तरफ से हमास पर शिकंजा कस रही है। नेतन्याहू ने कहा, हम हमास पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।

**आवश्यकता है**

उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले से प्रकाशित समाचार पत्र को समस्त जनपदों में एवम तहसील व ब्लॉक/शहर में ब्यूरो प्रमुख, चीफ रिपोर्टर, संवाददाता, प्रतिनिधि मण्डल की अवश्यकता है जिन्हे आकर्षण वेतन और भत्ते आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सम्पर्क सूत्र
शहर समता हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र
मोबाईल नम्बर. 9190052 39332
.919450482227

# ‘ईरान के साथ खराब समझौता नहीं करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप’, अमेरिकी वित्त मंत्री बोले- होर्मुज खुलना जरूरी



वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ किसी भी श्खराब समझौतेश को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समाधान होना चाहिए और होर्मुज जलडमरूमध्य में खुली शिपिंग की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास तनाव की वजह से लगभग 2,000 जहाज इस समय खाड़ी से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी पर निर्भर है समझौता ‘व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए स्कॉट बेसेंट ने साफ किया कि ईरान के साथ फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी समझौता राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, श्टीमें लगातार बातचीत कर रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है। ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा। उसे परमाणु हथियार रखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी और होर्मुज जलडमरूमध्य में मुक्त आवागमन जरूरी है। समुद्री मार्ग पहले की तरह खुला और स्वतंत्र होना चाहिए। सैन्य और आर्थिक दबाव से झुका ईरान वित्त मंत्री ने तर्क दिया कि हाल के अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ईरान बातचीत की मेज पर आया है। उन्होंने कहा, इस प्रशासन ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने वह किया है जो कोई और प्रशासन नहीं कर सका। हमने ईरानियों को उनके परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए तैयार किया है और शायद यह भी कि वे परमाणु हथियार न रखें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बेसेंट ने यह भी कहा कि किसी भी भविष्य की प्रतिबंधों में ढील तभी दी जाएगी जब ईरान अमेरिका की प्रमुख शर्तों को पूरा करेगा। ऊर्जा बाजार मजबूत वित्त मंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बावजूद ऊर्जा बाजार मजबूत बना हुआ है और शिपिंग बाधाएं खत्म होने के बाद तेल कीमतों में गिरावट आ सकती है। बेसेंट ने कहा कि तेल की कीमतें पहले की अपेक्षाओं से कम हैं और इसका श्रेय अमेरिका के बढ़ते उत्पादन को दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत से नतीजा नहीं निकला तो अमेरिका सरकार का धैर्य असीमित नहीं है। खाड़ी से निकलने का इंतजार कर रहे करीब दो हजार जहाजरू स्कॉट बेसेंट स्कॉट बेसेंट के खुलासे से पहली बार अंदाजा लगा है कि इस अहम समुद्री रास्ते पर कितना बड़ा जाम लग चुका है। दुनिया के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) का बड़ा हिस्सा आम तौर पर इसी रास्ते से गुजरता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि करीब 2,000 जहाज खाड़ी से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे ही शिपिंग दोबारा सामान्य होगी, दुनिया के बाजार इस स्थिति को संभाल लेंगे। एआई की रेस में चीन, अमेरिका से काफी पीछे अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया की अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पावर घोषित करते हुए तर्क दिया कि चीन अभी भी काफी पीछे है। वाशिंगटन इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिस्पर्धाओं में से एक में अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। बेसेंट ने कहा, श्अमेरिका विश्व में एआई का अग्रणी देश है। हम एक एआई महाशक्ति हैं। चीन दूसरे स्थान पर है, लेकिन काफी पीछे है।

## 300 अरब डॉलर निवेश से लेकर लेबनान में हमले रोकने तक, आखिर समझौते में क्या-क्या शामिल ?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को खत्म करने के लिए तैयार हो रही संभावित डील अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि दोनों पक्ष समझौते के काफी करीब हैं, हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है। अगर यह समझौता अंतिम रूप लेता है तो इसमें केवल युद्धविराम ही नहीं, बल्कि परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत, होर्मुज जलडमरूमध्य, लेबनान संकट और बड़े निवेश पैकेज जैसे कई अहम मुद्दे शामिल होंगे।

डील में क्या–क्या है?

1. 60 दिन का सीजफायर और बातचीत

प्रस्तावित समझौते के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों तक संघर्षविराम बढ़ाएंगे। इसी अवधि में दोनों देश स्थायी शांति समझौते और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विस्तृत बातचीत करेंगे।

2. होर्मुज जलडमरूमध्य खुलेगा

दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य करने का प्रस्ताव है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान समुद्री बारूदी सुरंगें हटाएगा, जबकि अमेरिका नौसैनिक प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार करेगा।

3. परमाणु कार्यक्रम पर सबसे बड़ी बातचीत

डील का सबसे संवेदनशील हिस्सा ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता दे। साथ ही समृद्ध यूरेनियम के भंडार और भविष्य में यूरेनियम संवर्धन के नियमों पर भी बातचीत होगी।

4. प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज संपत्तियां

समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत और विदेशों में फंसी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को लेकर भी चर्चा शामिल है। ईरान लंबे समय से अपने जमे हुए फंड तक पहुंच की मांग करता रहा है।

5. लेबनान युद्ध पर भी फोकस डील में लेबनान में जारी संघर्ष को कम करने और हिजबुल्ला व इस्राइल के बीच तनाव घटाने से जुड़ा प्रावधान भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि लेबनान को लेकर दोनों पक्षों की व्याख्या अलग–अलग बताई जा रही है।

6. ईरान के लिए 300 अरब डॉलर का निवेश पैकेज

डील का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा करीब 300 अरब डॉलर के अंतरराष्ट्रीय निवेश और पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव है। रिपोर्टों के अनुसार अंतिम समझौता होने पर अमेरिका ईरान में बड़े निवेश को सुगम बनाने में मदद कर सकता है। तेल, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों की एंट्री की संभावना भी जताई गई है। अभी किन मुद्दों पर अटका है मामला? हालांकि अमेरिका और ईरान समझौते के काफी करीब बताए जा रहे हैं, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी मतभेद बने हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुआ है। ऐसे में यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि दोनों देश समझौते के एक ही मसौदे पर काम कर रहे हैं या नहीं, और ईरान की ओर से अंतिम मंजूरी देने का अधिकार किसके पास है। सबसे बड़ा विवाद संघर्षविराम की शर्तों को लेकर है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार प्रस्तावित समझौता 60 दिनों के लिए लड़ाई रोकने और आगे की बातचीत का रास्ता खोलने पर केंद्रित है। वहीं ईरान का दावा है कि इसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति की घोषणा शामिल है और यह व्यापक स्थायी समझौते की दिशा में एक अंतरिम व्यवस्था होगी। होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी दोनों देशों की व्याख्या अलग–अलग है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि ईरान पहले समुद्री बारूदी सुरंगें हटाए और जहाजों की आवाजाही सामान्य करे, जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दी जाए। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि समझौते के तहत अमेरिकी नाकाबंदी 30 दिनों के भीतर हटा ली जाएगी और बातचीत के दौरान जलडमरूमध्य पूरी तरह खुला रहेगा।

## ‘ईरान-अमेरिका समझौते के करीब लेकिन अभी डील नहीं हुई है’, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान

मैरीलैंड (अमेरिका),एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने और दीर्घकालिक शांति स्थापित करने की दिशा में बातचीत अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। हालांकि, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है और यह कहना जल्दबाजी होगी कि अंतिम समझौता कब और क्या हो




पाएगा। जेडी वेंस ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोनों पक्ष कुछ बिंदुओं और विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन काफी करीब हैं और बातचीत जारी रहेगी। वेंस ने दावा किया कि अगर समझौता हो जाता है तो इससे होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से पूरी तरह खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले ही ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमताओं को काफी कमजोर कर चुका है और उसके परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय तक पीछे धकेलने की स्थिति में है। उनके अनुसार यह अमेरिकी जनता के हित में होगा। युद्धविराम बढ़ाने का प्रस्ताव रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में मौजूदा युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर औपचारिक वार्ता शुरू करने की योजना शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, लेकिन उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी नेतृत्व की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हालांकि, ईरान की अर्ध–सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी समझौते को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और न ही इसकी पुष्टि हुई है। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका लंबे समय से ईरान से उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन बंद करने और मौजूदा भंडार को खत्म करने की मांग करता रहा है। वाशिंगटन का मानना है कि इस सामग्री का उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। वेंस ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि ईरान इस बार अच्छी नीयत के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, अप्रैल में युद्धविराम लागू होने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप कई बार यह कह चुके हैं कि समझौता करीब है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। होर्मुज जलडमरूमध्य और प्रतिबंधों में राहत मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संभावित समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का प्रावधान हो सकता है। इसके तहत ईरान को 30 दिनों के भीतर समुद्री मार्ग में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना होगा। इसके बदले अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाने और ईरान को तेल निर्यात फिर से शुरू करने के लिए कुछ प्रतिबंधों में छूट देने पर विचार कर सकता है। ट्रंप ने नहीं दी अंतिम मंजूरी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप को प्रस्तावित समझौते की जानकारी दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर अंतिम मंजूरी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि वह आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला ले सकते हैं। इस बीच ईरान के सरकारी मीडिया में 14 बिंदुओं वाले एक कथित समझौता मसौदे की जानकारी सामने आई थी, जिसमें अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, ईरान के आसपास से अमेरिकी बलों की वापसी और होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य यातायात बहाल करने जैसे प्रावधान शामिल बताए गए थे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस दस्तावेज को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है। युद्धविराम उल्लंघन के आरोप समझौते की बातचीत के बीच दोनों देशों ने एक–दूसरे पर युद्धविराम उल्लंघन के आरोप भी लगाए हैं। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (प्ळब) ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। वहीं ईरानी मीडिया ने एक अमेरिकी विमान या ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड (ब्छज्ब्ड) ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी अमेरिकी विमान नहीं गिराया गया है और सभी हवाई संसाधन सुरक्षित हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तेल का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में तनाव और जलमार्ग के बंद होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को न केवल क्षेत्रीय शांति बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

### टेस्टिंग के दौरान फटा ब्लू ओरिजिन का रॉकेट, आसमान में दिखा खौफनाक मंजरय मस्क ने दी प्रतिक्रिया

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसका विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च पैड पर टेस्टिंग के दौरान अचानक विस्फोट का शिकार हो गया। यह घटना गुरुवार रात फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्थित लॉन्च कॉम्प्लेक्स–36 में हुई। रॉकेट में इंजन फायरिंग टेस्ट चल रहा था, तभी तेज धमाके के साथ आग का बड़ा गोला आसमान में दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई इलाकों में घर तक हिल गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने धमाके की तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिनमें आसमान नारंगी रंग की आग से चमकता नजर आया। कंपनी ने सभी कर्मचारियों के सुरक्षित होने की दी जानकारी ब्लू ओरिजिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि टेस्ट के दौरान तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। कंपनी के मुताबिक, सभी कर्मचारियों की गिनती कर ली गई है और कोई भी घायल नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा कि आज के हॉटफायर टेस्ट के दौरान हमें एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा। मामले की जांच की जा रही है और जल्द अपडेट साझा किया जाएगा। स्थानीय आपातकालीन अधिकारियों ने भी साफ किया कि विस्फोट के बाद किसी जहरीले धुएं या अन्य खतरे की आशंका नहीं है। स्पेसएक्स के मालिक और अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने इस घटना पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए लिखा श्बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। रॉकेट कठिन होते हैं। ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन रॉकेट पहले भी तकनीकी समस्याओं को लेकर चर्चा में रहा है। अप्रैल में इसकी उड़ान को रोक दिया गया था क्योंकि इंजन फेल होने के कारण यह एक सैटेलाइट को गलत कक्षा में छोड़ बैठा था। यह न्यू ग्लेन रॉकेट की केवल तीसरी उड़ान मानी जा रही थी। ब्लू ओरिजिन इस भारी–भरकम रॉकेट का इस्तेमाल नासा के चंद्र मिशनों के लिए लैंडर लॉन्च करने में करना चाहता है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन लंबे समय से एलन मस्क की स्पेसएक्स को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। न्यू ग्लेन रॉकेट को कंपनी के भविष्य के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। इस रॉकेट का नाम अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी के रूप में इतिहास रचा था।

### पश्चिम एशिया संकट: एनएसए डोभाल बोले- तनाव से डगमगाया वैश्विक व्यापार, भारत शांति बहाल करने के लिए तैयार

मॉस्को, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। मॉस्को में आयोजित सुरक्षा मामलों के उच्च पदस्थ अधिकारियों की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक व्यापार को बिना किसी बाधा के जारी रखने की जोरदार वकालत की।

उन्होंने खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। अजीत डोभाल ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष का जिक्र करना इस समय बेहद जरूरी है। क्षेत्र में जारी तनाव गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। समुद्री यातायात पर मंडराता खतरा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में आ रही रुकावटें यह दर्शाती हैं कि मौजूदा स्थिति कितनी नाजुक है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर के जरिए होने वाला अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है।

प्रतापगढ़ ब्यूरो
शरद कुमार श्रीवास्तव
7/31, अचलपुर, प्रतापगढ़

संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।